

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> सुशासन व पारदर्शिता के साथ...



जामिया यूनिवर्सिटी में ‘फ्री कश्मीर’ के नारे

छात्रसंघ की आड़ में देशविरोधी एजेंडा

नई दिल्ली। की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब ऐसे विवादों के घेरे में आ गया है, जिनका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन ही नहीं, प्रदर्शनकारियों और उनके राजनीतिक समर्थकों को भी देना होगा। देखा जाये तो विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों पर ‘फ्री कश्मीर’ और ‘फ्री शरजील इमाम’ जैसे नारे लिखे मिलने के बाद सवाल उठना लाजिमी है कि छात्रसंघ चुनाव की मांग करने वाले आंदोलन में आखिर कश्मीर और शरजील इमाम की रिहाई जैसे मुद्दे किस उद्देश्य से जोड़े जा रहे हैं?

छात्रसंघ चुनाव की बहाली अपने आप में एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसके नाम पर परिसर में ऐसे नारे सामने आना, जो देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें किसी भी स्तर में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आंदोलन का उद्देश्य चुनाव कराना है, तो ‘फ्री कश्मीर’ का नारा किस मांग का प्रतिनिधित्व करता है?



क्या प्रदर्शनकारी इस नारे की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? और यदि नहीं, तो विश्वविद्यालय की दीवारों पर इसे लिखने वालों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग वे स्वयं क्यों नहीं करते?

हम आपको याद दिला दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ 2006 में परिसर में हिंसा और उससे पढ़ाई में आए व्यवधान के बाद भंग कर दिया गया था। अब प्रदर्शनकारी 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। 12 अक्टूबर से भूख

हड़ताल और धरना जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले पर विचार करने के लिए समिति भी गठित की है। लेकिन इस आंदोलन के बीच लिखने वालों की पहचान सार्वजनिक करने का अवसर बनता जा रहा है? देखा जाये तो छात्रों को राजनीतिक मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जाने से सभी को बचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि क्या

छात्रसंघ बहाली की मांग को कुछ लोग अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने और विवादित नारेबाजी का मंच बना रहे हैं? यदि ऐसा है, तो आंदोलन के आयोजकों को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता चुनाव है या परिसर में वैचारिक टकराव को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद ने एक दिन पहले दीवार फांदकर परिसर में प्रवेश किया और वहां का माहौल बिगाड़ा। प्रशासन के मुताबिक, उनके दौरे के बाद तनाव बढ़ा और इस संबंध में दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। यहां सवाल उठता है कि क्या छात्र आंदोलन राजनीतिक दलों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने का अवसर बनता जा रहा है? देखा जाये तो छात्रों को राजनीतिक मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जाने से सभी को बचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि वह छात्र हित में ही वहां गये थे।

जेएनयू की दीवारों पर विवादित नारे

राजधानी दिल्ली के दो प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में परिसरों की दीवारों पर विवादित और भड़काऊ नारे लिखे जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पहले जामिया और अब जेएनयू में हुई इन घटनाओं से शैक्षणिक संस्थानों का माहौल एक बार फिर गरमा गया है, जिससे छात्र संगठनों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। जेएनयू परिसर में वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण एवं शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करने के आरोप सामने आए हैं। परिसर की दीवारों पर ‘फ्री उमर ख़ालिद’ और ‘लॉन्ग लिव नक्सलबाड़ी’ जैसे नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा, सामने आई तस्वीरों में आइसा के कैडर द्वारा वीर सावरकर के चित्र के साथ आपत्तिजनक लेखन किए जाने का मामला भी प्रकाश में आया है। एबीवीपी जेएनयू इकाई ने वामपंथी छात्र संगठनों और जेएनयूएसयू की राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि छात्र हितों से जुड़े वास्तविक मुद्दों को उठाने के बजाय परिसर में ऐसे नारों को बढ़ावा देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उमर ख़ालिद वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में हैं।

भारत यूरोप को दनादन कर रहा गोला-बारूद सप्लाई

नई दिल्ली।भारत के डिफेंस सेक्रेटरी का यह बयान काफी चर्चा में है, जहां वह बता रहे हैं कि भारत यूरोप को हथियार गोला बारूद एक्सपोर्ट करने वाला तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। वही भारत जो अपनी सैन्य जरूरतों के लिए कभी दुनिया भर की ओर टकटकी लगाकर देखता था वो भारत आज यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन चुका है और इसका ऐलान भी खुद भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया है। केपीएमजी अग्रसर भारत मंच के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा सचिव ने यह बड़ा ऐलान किया और बताया कि यूरोपीय देशों में चल रहे रीआर्म यूरोप अभियान और भारत के मजबूत होते घरेलू डिफेंस इकोसिस्टम के दम पर भारत अचानक से यूरोप को सैन्य साजो सामान और हथियार सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने मौजूदा वैश्विक हालात और भारत की मौजूदा वैश्विक हालात और भारत की छलांग को समझाते हुए कहा कि



दुर्भाग्यवश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष और भू राजनीतिक अनिश्चितता के कारण हथियारों की होड़ बढ़ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सक्रिय संघर्षों की संख्या आज अपने उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में हथियारों का व्यापार बढ़ना स्वाभाविक है। भारत परंपरागत रूप से बड़ी मात्रा में पारंपरिक गोला बारूद और तोपों के 155 मि.मी. गोले निर्यात करता रहा है। अचानक भारत यूरोप को हथियार निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और इसकी मुख्य वजह है आर्टिलरी शेल्स यानी कि तोप के गोलों की जबरदस्त मांग। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बताते हैं कि भारत का कुल रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ यानी कि लगभग 3.6 बिलियन यूरो के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है।



प्रदेश की लोकसंस्कृति को देश-दुनिया में प्रतिष्ठित किया : विष्णुदेव

दुर्ग। छत्तीसगढ़ लोककला और संस्कृति की समृद्ध धरती है। हमारी लोककलाएं हमारे इतिहास, जीवन-मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। इन्हें सहेजना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार लोककलाओं के संरक्षण-संवर्धन के साथ कलाकारों को प्रोत्साहन और व्यापक मंच उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के अहिंवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बानबरद में आयोजित पंडवानी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने प्रदेशभर से आए लोक कलाकारों का अभिनंदन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी ने अनेक महान कलाकार दिए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और साधना से प्रदेश की लोकसंस्कृति को देश-दुनिया में प्रतिष्ठित किया है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

चंद्रबाबू नायडू-वाईएसआरसीपी निकाय चुनावों में आमने-सामने

अमरावती। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान कथित हिंसा और उम्मीदवारों को नामांकन से रोकने के आरोपों को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) पर हिंसा और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया है। वहीं, वाईएसआरसीपी ने सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की सरकार पर पुलिस और राज्य निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत कर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के दावों पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को उंडावल्ली स्थित अपने कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी ने पुंगनूर, दासरी, कडपा, थंबल्लापल्ले और तिरुपति समेत कई जगहों पर अशांति फैलाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों पर हमले किए और वाहनों में आग लगाई। नायडू ने यह भी आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी के एक सांसद ने अपने वाहन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश की।

निकाय चुनाव : भाजपा अकेले लड़ेगी कोलकाता-हावड़ा में

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति स्पष्ट करनी शुरू कर दी है। पार्टी नेता राहुल सिन्हा ने शनिवार को कहा कि भाजपा दोनों शहरों में स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी और नगर निगम स्तर पर किसी अन्य दल के साथ उसका चुनावी गठबंधन नहीं है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने एनसीपीआई के साथ संभावित तालमेल की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया। वहीं, राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने दावा किया कि इन चुनावों के नतीजे विधानसभा चुनावों की तरह भाजपा के पक्ष में एकतरफा हो सकते हैं। ऐसे में दोनों नगर निगमों के चुनाव से पहले गठबंधन और उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल दलों के साथ भाजपा का लोकसभा और राज्यसभा स्तर पर चुनावी तालमेल है, लेकिन नगर निगम स्तर पर ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब एनसीपीआई के नेताओं की ओर से स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन की मांग की जा रही है।

आजमगढ़ में विकास यादव का नाम 13 बार वोट लिस्ट में लखनऊ

आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में विकास यादव का नाम 13 बार दर्ज होने पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रकरण में दोषी पाए गए कम्प्यूटर सहायक और 5 बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची के काम से तत्काल हटाते हुए उनकी सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 2 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 15 अक्टूबर को प्रेसवार्ता कर इस संबंध में गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें असली विकास यादव को मीडिया के सामने पेश भी किया गया था। इसका संज्ञा लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आजमगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट ली। समान नाम व समान वल्र्दयत का एक मतदाता गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्र चौरीचौरा से संबंधित है।



यूपी में भाजपा को सहयोगियों से भिन्नता का खतरा

लखनऊ। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा के सामने अब विपक्ष से मुकाबले के साथ अपने ही नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधने की चुनौती खड़ी हो गई है। संगठन में पद और जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे कार्यकर्ताओं की अनदेखी तथा दूसरे दलों से आए नेताओं को तरजीह देने की नीति पार्टी के भीतर असंतोष की वजह बन रही है। हालात यह हैं कि चुनावी तैयारियों के सिलसिले में दौरे पर पहुंच रहे बड़े नेताओं के सामने भी नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा सामने आने लगा है। ऐसे में सत्ता की हैट्टिक लगाने के लक्ष्य के बीच भाजपा को भीतरघात का खतरा परेशान कर सकता है। भाजपा ने संगठन को खुली मोड में लाने के लिए बैठकों, दौरों का सिलसिला तेज कर दिया है। हर बैठकों में बड़े नेता कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताने से नहीं अछा रहे हैं। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि संगठन और विभिन्न मोर्च व प्रकोष्ठों में समायोजन न होने से वर्षों से पार्टी की सेवा में जुटे तमाम कार्यकर्ताओं में असंतोष गहराता जा रहा है। कई बैठकों में पीक एंड चूज और सेंटिंग-गेटिंग के सिद्धांत पर ही पदाधिकारियों के चयन के आरोप लग रहे हैं।

दिल्ली में 10 साल में 24 अक्टूबर को दर्ज हुई सबसे साफ हवा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में बड़ा सुधार देखने को मिला है। दिल्ली सरकार के अनुसार, शनिवार को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 191 दर्ज किया गया, जो कोविड काल को छोड़कर पिछले एक दशक में 24 अक्टूबर के लिए सबसे कम है। यह एक्यूआई मध्यम श्रेणी में आता है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस सुधार का श्रेय प्रवर्तन, निरंतर निगरानी और जनभागीदारी को दिया है। सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ अपने अभियान को वॉर मोड में जारी रखते हुए कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने पर लगभग 9,883 वाहन चालान जारी किए गए। धूल को नियंत्रित करने के लिए 2,810 किलोमीटर लंबी सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग (मशीन से सफाई) की गई और 1,075 किलोमीटर क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया गया। सरकार प्रदूषण के स्रोतों पर कड़ी नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस प्रणालियों, सीसीटीवी निगरानी और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग से लैस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए प्रदूषण स्रोतों को ट्रैक किया जा रहा है।

अरब स्प्रिंग 2.0

अभिनय आकाश

यूरोप की जो दुनिया को तरक्की, ताकत और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है। आज उसी यूरोप की सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है। फ्रांस से सर्बिया, इटली से स्पेन समेत यूरोप के कई देशों तक महंगाई, बेरोजगारी और मकानों के आसमान छूते किराए से युवा परेशान है। सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस से टकराव और अब विरोध का कैलेंडर। ऐसे में सवाल है क्या यूरोप में 2010 जैसी अरब स्प्रिंग की आहट सुनाई देने लगी है? फ्रांस से जो हिंसा शुरू हुई, जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो धीरे-धीरे यूरोप के और भी कई देशों में फैल चुका है। कहीं

युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो कहीं महंगाई और बेरोजगारी ने सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो रही हैं, जबकि कुछ देशों में छात्र आंदोलन इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां वे चुनावी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक युवा सड़कों पर हैं और सरकारों के प्रति जनता का आक्रोश साफ देखा जा सकता है। फ्रांस से लेकर सर्बिया और इटली से लेकर इंडोनेशिया तक, कई देशों में छात्र आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया है। युवा भ्रष्टाचार, महंगाई और बदहाल शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर

सरकारों से जवाब मांग रहे हैं। फ्रांस में छात्र प्रदर्शनों के बीच एक नारा काफी चर्चा का विषय बन गया है—बिस्मिल्लाह से ले तेन्नरे , जिसका अर्थ निकाला गया ईश्वर के नाम पर, यह अंधकार है। दावा किया जाता है कि यह वाक्यांश सोशल मीडिया पर एक मैसेज के स्क्रीनशॉट से निकला। हालांकि, फ्रेंच भाषा में यह कोई व्याकरण के अनुसार सही वाक्य नहीं है, फिर भी अपनी अजीबोगरीब बनबट और शब्दों के अनूठे मेल के कारण यह लोगों की जुबान पर चढ़ गया। ठीक इसी तरह भारत में भी जुलाई देशों के छात्र आंदोलनों के दौरान एक स्लैंग वास्ते गुनाह्मा वायरल हुआ था, जिसका अपना कोई खास मतलब नहीं था।



न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस का यह नारा सबसे पहले स्नैपचेट पर सामने आया। वहां एक शख्स ने छात्र प्रदर्शनकारियों के प्राइवेट चैट ग्रुप में शामिल होने के लिए अलग-अलग प्रोफाइल बनाकर लोगों को संदेश भेजे थे। उस मैसेज में उसने लिखा था बिस्मिल्लाह से ले तेन्नरे, और उसके आगे लिखा था हम सब कुछ तोड़

देंगे। कुछ यूजर्स को इस मैसेज की भाषा अजीब और मजाकिया लगी, जिसके बाद उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। धीरे-धीरे यह जुमला वायरल होकर प्रदर्शनकारियों के पोस्टरों तक पहुंच गया। दूसरी तरफ, इटली में विरोध-प्रदर्शनों की स्थिति और भी गंभीर नजर आ रही है। बोलीगना में नकाबपोश प्रदर्शनकारियों, वामपंथी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़पों की खबरें हैं, जहां बैरिकेड्स जलाने और लिखा था बिस्मिल्लाह से ले तेन्नरे, और की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं, ईधन

की बढ़ती कीमतों को लेकर इटली में झड़पों की राखवापी हड़ताल ने आर्थिक संकट की आशंका बढ़ा दी है। दक्षिणी इटली के कई इलाकों के पेट्रोल पंपों पर ईंधन की भारी क्लिश्त हो गई है। सुपरमार्केट में ताजे फल-सब्जियों और वाइनाज की सप्लाई ठप पड़ने लगी है, और कैप्री तथा इस्त्रिया जैसे द्वीपों की फेरी सेवाएं बाधित होने का खतरा मंडा रहा है। ऐसे हालात में सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। पोलैंड में भी बड़े पैमाने पर लोग विधायी सुधारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और देश की संसद प्रजनन अधिकारों से जुड़े

अपने वादों को पूरा करें। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र सरकारी जवाबदेही और अधूरे चुनावी वादों को लागू कराना है। ग्रीस में भी एक बेहतर शिक्षा प्रणाली की मांग को लेकर हजारों छात्र और शिक्षक लाभबंद हैं। एथेंस में करीब 10,000 लोगों ने मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाया जाए, स्कूलों की हालत सुधारी जाए, शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए और युवाओं को भी बड़े पैमाने पर लोग विधायी सुधारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और देश की संसद प्रजनन अधिकारों से जुड़े

बस्तर दशहरा विवाद: जिसने निभाई नहीं रस्म, उसने कर ली राष्ट्रपति से मुलाकात

पनका समाज में भारी नाराजगी

जगदलपुर।बस्तर दशहरा 2026 आए दिन विवादों में घिरा रहा। अब राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे के बाद काछन गादी रस्म से जुड़े पनका जाति के प्रतिनिधियों की नाराजगी सामने आई है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में लगे दशहरा उत्सव की प्रतीकात्मक प्रदर्शनी में पीहू दास के स्थान पर दूसरी बच्ची को राष्ट्रपति से मिलवाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि राष्ट्रपति से पनका जाति के लोगों को मुलाकात का अवसर नहीं दिया गया। 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा में इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं। जगदलपुर के लालबाग मैदान में दशहरा उत्सव में निभाए जाने वाली सभी रस्मों पर आधारित प्रतीकात्मक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने काछन गादी रस्म की प्रदर्शनी में एक



बच्ची से भी मुलाकात की। काछन गादी रस्म को निभाने वाले पनका जाति ने इसपर आपत्ति जताई है। दरअसल, काछन गादी रस्म के तहत पीहू दास पिछले तीन साल से कांटों के झूले पर लेटकर काछन देवी की भूमिका निभा रही हैं। इस रस्म के दौरान वह राजपरिवार के सदस्यों को दशहरा मनाने की अनुमति देती हैं। वहीं लालबाग मैदान में आयोजित दशहरा

उत्सव कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी में उनकी जगह दूसरी बच्ची से राष्ट्रपति की मुलाकात कराने को लेकर पनका जाति के प्रतिनिधियों ने गहरी नाराजगी जताई है। इस मामले में बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष एवं बस्तर सांसद महेश कश्यप का कहना है कि दशहरा प्रदर्शनी में प्रतीकात्मक चित्रण के दौरान मूल बच्ची को खड़ा करने से काछन देवी का अपमान

होता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सीमित लोगों की ही भूमिका हो पाई। सांसद ने मुरिया दरबार में पनका जाति के लोगों की उपस्थिति की बात भी कही। उनका आश्वासन दिया कि पनका जाति के जनप्रतिनिधियों की नाराजगी को दूर करने के लिए वह दिल्ली में राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि राष्ट्रपति का बस्तर दशहरा में शामिल होना शुभ संकेत है, लेकिन शासन-प्रशासन परंपराओं को बिगाड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने काछन देवी की परंपरा, जोगी को समय से पहले हटाने और रथ निर्माण करने वालों को पहले ही छुट्टी देने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को इस परंपरा की जानकारी देकर पनका समाज और काचन देवी की परंपरा से जुड़ी बच्ची को उनसे मिलवाया

जा सकता था। बघेल ने पनका समाज की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि वे समाज के साथ हैं। इस घटनाक्रम से नाराज मुख्य पुजारी गणेश दास ने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने इसे धोखेबाजी बताते हुए कहा कि बैठायी किसर्जन और को जा रहा है और राष्ट्रपति से मुलाकात किसी दूसरी बच्ची को कराई जा रही है। मुख्य पुजारी ने साफ किया कि वह बच्ची न तो उनके परिवार की है और न ही वे उसे जानते हैं। पनका जाति के प्रतिनिधियों ने कहा कि परंपरा के मुताबिक, 24 अक्टूबर को जिस कांटे के झूले को विसर्जित किया जाना था। लेकिन अब वह विसर्जन नहीं करेंगे। जिस बच्ची ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, वही विसर्जन करेंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो वह अगले बस्तर दशहरा से दूरी बना लेंगे। इस रस्म में शामिल नहीं होंगे।

भिलाई ननि चुनाव 2026: तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने की बड़ी बैठक



■ **पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फिर से कांग्रेस का महापौर हम भिलाई नगर निगम में बनाएंगे.**

भिलाई। नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिसंबर में प्रस्तावित भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को बड़ी बैठक की। बैठक में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और जीत का दावा भी कर दिया। चुनावी बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पर्यवेक्षक धनेंद्र साहू, सह-मंत्री ताम्रध्वज साहू, भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव, महापौर नीरज पाल समेत कांग्रेस के पार्षद और बड़ी संख्या में नेता-कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। बैठक के जरिए एक तरह से पार्टी ने अपना नगर निगम चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। चुनाव तैयारियों को लेकर हुई इस बैठक में पूर्व

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति, बूथ स्तर पर सक्रियता और अधिक से अधिक पार्षदों को जिताने के लिए जरूरी टिप्स दिए। कांग्रेस फिलहाल भिलाई नगर निगम में सत्ता में है और इस बार भी महापौर पद पर कब्जा बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। भूपेश बघेल ने दावा किया कि आगामी चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का महापौर बनेगा और बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षद जीतकर आएंगे। धान खरीदी को लेकर विधायक भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक मधान खरीदी को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। पूर्व सीएम का आरोप है कि किसानों का धान समय पर खरीदा जाता तो किसान भी बेहतर तरीके से दिवाली मना पाते। भाजपा पर हमला बोलते हुए भूपेश बघेल ने बेरोजगारी, वोट चोरी, जीएसटी और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा।

शहर का सितारा बनकर चमकेगा कोरबा का मानिकपुर पोखरी



■ **45 करोड़ से भव्य पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी**

कोरबा। शहर के हृदय स्थल में स्थित ऐतिहासिक मानिकपुर पोखरी जल्द ही एक पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में नजर आएगी। जिला प्रशासन और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संयुक्त पहल से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। पहले इस योजना का बजट 11 करोड़ रुपये तय किया गया था, जिसे अब विस्तृत स्वरूप देते हुए बढ़ाकर 45 करोड़ रुपये कर दिया गया है। परियोजना का निर्माण कार्य नए साल में जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है।

सालों पहले मानिकपुर पोखरी के प्रोमोशन और एक नई चौपाटी बनाने की योजना पर नगर पालिक निगम ने काम शुरू किया। जिला प्रशासन भी ये मानता है कि यह योजना लंबे वक्त से पाइपलाइन में रही। शहर के लिए मानिकपुर पोखरी पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुप्रतीक्षित

योजना है। शहर के करीब ही पर्यटन क्षेत्र विकसित होने से कोरबा के लोगों को नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन शहर के पास मिल पाएगा। कोरबा में पहले से ही कई पर्यटन केंद्र हैं जो टूरिस्टों की पहली पसंद हुआ करते हैं। अब एक नया पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है, जो शहर के बिल्कुल करीब होगा, जहां पहुंचना आसान होगा। जिले के लिए ?मानिकपुर पोखरी का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यह कभी कोरबा जिले की पहली ओपनकास्ट कोयला खदान हुआ करती थी। लगभग 23 एकड़ में फैली इस खदान में वर्ष 1966 में सौवियत रूस के तकनीकी सहयोग से खनन कार्य शुरू किया गया था। लगभग 24 वर्षों तक निर्बाध उत्खनन के बाद, जब खदान का गहराई 100 मीटर तक पहुंची, तब अचानक भूजल का भारी स्रोत फूट पड़ा। ?पानी की आवक इतनी तेज थी कि उस समय की आधुनिक पंपिंग प्रणाली भी विफल हो गयी और खदान जलमग्न हो गया।

सूरजपुर में नगर पंचायत सीएमओ को हटाने की मांग कि

■ **प्रेमनगर के जनप्रतिनिधियों ने दी चेतावनी**

सूरजपुर। नगर पंचायत प्रेमनगर के जन प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मिलकर सीएमओ को उनके पद से हटाने की मांग रखी है। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सीएमओ अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रहे हैं। सीएमओ की कार्यशैली से नाराज नगर पंचायत अध्यक्ष सखमनिया जगत, उपाध्यक्ष आलोक साहू सहित कई पार्षद एकजुट होकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर सभी ने एकसुर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (एड्यू) को उनके पद से हटाने की मांग की। नाराज पार्षदों का आरोप है कि सीएमओ न सिर्फ अपने पद का



दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि नगर में होने वाले विकास के कार्यों को भी प्रभावित कर रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि अगर वो कामों को यूं ही प्रभावित करते रहे तो जनहित से जुड़े मुद्दों पर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसको कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर सभी ने एकसुर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (एड्यू) को उनके पद से हटाने की मांग की। नाराज पार्षदों का आरोप है कि सीएमओ न सिर्फ अपने पद का

धमतरी मराठापारा और बांसपारा बवाल केस, मराठा समाज ने पुलिस से की मुलाकात, मांगी जानकारी

धमतरी। शहर के मराठापारा और बांसपारा में आधी रात को हुए बवाल और हंगामे पर मराठा समाज गुस्से में है। गुरुवार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद शुक्रवार को समाज के महिला-पुरुष और पदाधिकारी बड़ी संख्या में कोतवाली थाना पहुंचे। समाज ने पुलिस से कार्रवाई की जानकारी लेते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने समाज की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मराठा समाज के मुताबिक, 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात को



यह हंगामा हुआ। करीब 20 से 22 युवक चेहरे पर गमछा और स्कार्फ बांधकर लाठी-डंडों और हथियारों के साथ मराठापारा और बांसपारा की गलियों में पहुंचे। इस दौरान युवकों पर गाली-गलौज कर मोहल्ले में दहशत फैलाने की कोशिश करने का आरोप है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ गई है।

घटना के विरोध में गुरुवार को मराठा समाज ने कोतवाली थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की थी। समाज ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो धमतरी बंद और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी सिलसिले में शुक्रवार को समाज के लोग फिर थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी।दीपक तोलें ने कहा कि रात के समय 20 से 22 युवक चेहरे ढंककर लाठी-डंडों और हथियारों के साथ मोहल्ले में घूम रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे।

धमतरी का मुजगहन हत्याकांड: 3 और आरोपी गिरफ्तार



धमतरी। चर्चित मुजगहन हत्याकांड में पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। जांच के दौरान अर्जुनी पुलिस ने पूर्व सरपंच चंद्रशेखर साहू के बेटे दीपांशु साहू की हत्या के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल स्प्रिंगदार चाकू, बांस का डंडा और कपड़े भी जब्त किए।

दरअसल, घटनाक्रम 21 अक्टूबर की रात की है, जब ग्राम मुजगहन में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों पर हमला किया गया था। शिकायत के मुताबिक, रात करीब 10:20 से 10:30 बजे के बीच

रत्नाबांधा और पंचवटी कॉलोनी क्षेत्र के कुछ युवकों ने सुदामा साहू के घर के सामने मुख्य मार्ग पर दीपांशु साहू और विकास साहू के साथ मारपीट की। इस दौरान डंडे और धारदार चाकू से हमला किए जाने का आरोप है। हमले में गंभीर रूप से जख्मी दीपांशु को जिला अस्पताल धमतरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि हमले में जख्मी विकास साहू का इलाज अभी जारी है।

अर्जुनी पुलिस ने 22 अक्टूबर को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 23 अक्टूबर को तीन अन्य आरोपियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शंकर नागरची (19), तामेश्वर नागरची उर्फ मोनू (19) और धनेश्वर नागरची (22) के नाम शामिल हैं। तीनों आरोपी रत्नाबांधा क्षेत्र के निवासी हैं। इससे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम फनेश्वर नेताम (18), रितेश नेताम (22), लिलेश उर्फ लिलेश्वर नेताम (20) और नोहर यादव उर्फ काला (23) हैं। ये सभी रत्नाबांधा क्षेत्र के निवासी हैं। इस तरह पुलिस अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

13.79 लाख से ज्यादा का गांजा जब्त 4 आरोपी गिरफ्तार

पिथौरा। महासमुंद्र में गांजा तस्करी पर कार्रवाई अब तक जारी है। 23 अक्टूबर की रात एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स को मुखबिर से सूचना मिली की 4 युवक पीढ़ू बैग में गांजा लेकर पैदल उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। सूचना पर एक्शन लेते हुए एनएच-53 रोड ग्राम रेहटीखोल के पास घेराबंदी की गई और चारों को पकड़ा गया। वहीं जब उनके पीढ़ू बैग की तलाशी ली गई, तो उसके अंदर 27.590 किलो अवैध गांजा मिला। बरामद गांजे की कीमत 13,79,500 रुपये आंकी गई। साथ ही उनके कब्जे से 4 मोबाइल भी जब्त किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गांजा को फुलबानी, जिला कंदमाल, उडिसा से अहमदाबाद गुजरात लेकर जा रहे हैं। आरोपी का कुटुंब अपराध धारा 20(B)(i)(C), एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर थाना सिंघोडा में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी रणछोड पटेल, प्रवीण कुमार पटेल, संजय सिंग, नारायण वाराडी,

हाथियों का तांडव- सुबह 3 बजे गांव में मची चीख-पुकार

लोरमी। लोरमी वनांचल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमुनाही में शनिवार तड़के हाथियों के एक झुंड ने भारी उत्पात मचाकर भारी तबाही मचाई है। हाथियों के अचानक पहुंचने से पूरे गाँव में दहशत का माहौल बन गया। झुंड ने जहाँ ग्रामीणों के मकानों को तहस-नहस कर दिया, वहीं खूंटे से बंधे बेजुबान मवेशियों को बेरहमी से कुचलकर मार डाला। गनीमत यह रही कि समय रहते ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचा ली। प्रास जानकारी के अनुसार, घटना तड़के सुबह लगभग 3 बजे की है। ग्राम जमुनाही निवासी नीलकंठ यादव को अचानक हाथियों के चिंचाड़ने की तेज आवाज सुनाई दी। जब नीलकंठ ने सतर्क होकर घर से बाहर निकलकर टॉर्च की रोशनी से देखा, तो उनके होश उड़ गए. हाथियों का एक बड़ा झुंड सीधे उनके घर की तरफ बढ़ रहा था। खतरे की गंभीरता को देखते हुए नीलकंठ ने बिना एक पल गंवार तुरंत अपनी हथी और बच्चों को जगाया और आनन-फानन में घर छोड़कर बस्ती की सुरक्षित जगह की ओर भाग निकले।

बीएसपी पार्षद समेत 4 दोस्तों की शराब पीने के बाद बिगड़ी तबियत

जांजगीर चाम्पा। जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शराब पीने से पार्षद समेत दो लोगों की मौत हो गई। तबियत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना से हड़कंप मच गया है। यह पूरा मामला पामगढ़ नगर पंचायत का है। मृतकों की पहचान ब्रह्मपार्षद राम खिलावन जांगड़े और जोहित खरे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने शुक्रवार रात 10 बजे पुसता अस्पताल पामगढ़ परिसर में अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब पी थी, जिसके कुछ देर बाद 3 की तबियत बिगड़ गई। आनन-फानन में खिलावन और जोहित को पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया। खिलावन जांगड़े ने सिस्म में, तो जोहित खरे ने अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। शराब में जहर होने की आशंका जताई जा रही है।

इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला: भाई-बहन बचाई जान

कोरबा। कोरबा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी में सवार भाई और बहन ने जैसे-तैसे कूदकर अपनी जान बचाई वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, पीयूष कंवर और उसकी दीदी कुसमुंडा से कटकोडबरी लौट रहे थे। इसी दौरान भिलाईबाजार तालाब के पास उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद दोनों भाई-बहन ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी स्कूटी जलकर खाक हो गई। इधर इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि आग कीतनी भयानक है और स्कूटी धू-धूकर जल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले कटघोरा कॉलेज के पास भी इसी तरह इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगी थी। लगातार हो रही घटनाओं से इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

धमतरी में एआई मिशन और एआई संगवारी की शुरुआत

धमतरी। केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी हैं और उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसे लेकर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई। महासमुंद्र लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में करीब चार घंटे चली बैठक में विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान अधूरे निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करने, शिकायतों का गंभीरता से निराकरण करने और योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक में धमतरी एआई मिशन सहित चार नई जनकल्याणकारी पहलों की शुरुआत भी की गई। इस मौके पर सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि दिशा समिति की बैठक हर तीन महीने में आयोजित की जाती है, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

पावर ग्रिड लगाने किसानों की जमीन छीनने की तैयारी

■ **45 करोड़ से भव्य पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी**

सक्ती। जिले के सपिया गांव में इन दिनों किसान अपनी कृषि भूमि को लेकर चिंता में डूब गए हैं। अधिकारियों ने पावर ग्रिड की स्थापना करने छोटे से सपिया गांव को चुना है, जहां छोटे-छोटे किसान खेती किसानी के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब उनके जीवन यापन का एक मात्र सहारा उनकी कृषि भूमि को अधिकारियों की नजर लगा गई है। पावर ग्रिड स्थापित करने छोटे किसानों की जमीन पर सर्वे शुरू कर दिया गया है। हैरत की बात यह है कि अधिकारी इसकी जानकारी किसानों को भी देना जरूरी नहीं समझ रहे। गुपचुप तरीके से कुछ दलालों को लेकर उनकी जमीनों पर सर्वे कार्य



किया जा रहा है। किसानों को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने कलेक्टर से उनकी जमीन को न लेने की गुजारिश की। किसानों ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि उनके गांव की अधिकांश भूमि 100 एकड़ पहले ही करंपाली जलाशय बांध के लिए और जल संसाधन विभाग के नहर निर्माण के लिए 150 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है, जिससे गांव का कृषि रकबा बहुत कम हो चुका है। अब पावर ग्रिड के लिए फिर से ग्राम सपिया, फगुम और अंजोरीपाली की कुल

165 एकड़ भूमि प्रस्तावित है। इसके बाद गांव में कृषि भूमि नहीं बचेगी। किसानों के जीवन यापन का एक मात्र सहारा उनकी जमीन है, जिसे शासन-प्रशासन छीन लेना चाहती है। किसानों का कहना है कि हम सब बार बार अधिकारियों से हमारी जमीन न लेने की गुजारिश कर रहे हैं। हमने रायपुर जाकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद और क्षेत्रीय विधायक सबको जापन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। अगर जनप्रतिनिधि और अधिकारी हमारा निवेदन नहीं सुन सकते तो फिर मजबूरन हमें आंदोलन करने सड़क पर उतरना होगा।ग्राम सपिया पहुंचे चंद्रपुर से कांग्रेस के विधायक रामकुमार यादव ने कहा कि आज हम लोग ग्राम पंचायत सपिया में आए हैं। यहां पावर ग्रिड लग रहा

है। यहां के किसान कल कलेक्टर के पास जापन देने गए थे। इनका कहना है कि हम लोग पहले ही बांध में हमारी 200-250 एकड़ जमीन चली गई, फिर नहर बनने में 200 एकड़ जमीन चली गई, उसमें भी पानी नहीं मिला और जो बची-खुची उपजाऊ जमीन है, डबल फसल वाली जमीन है, उसमें अभी पावर ग्रिड बना रहे हैं। इसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों ने बोला है कि हम मर जाएंगे पर जमीन नहीं देंगे।

विधायक यादव ने कहा, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं और जल संसाधन विभाग और पावर ग्रिड के बड़े-बड़े अधिकारी आ रहे हैं, नाप-जोख कर रहे हैं। किसान बेचारा क्या करेगा? किसान तो अपना हक के लिए आंदोलन करता है।

कवर्धा। कबीरधाम जिले के

कुमान गांव में पांच आदिवासी बैगा बच्चों की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। शुक्रवार को कांग्रेस के छह सदस्यीय दल ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दल में चार विधायक एक पूर्व विधायक, जिलाअध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने बच्चों की मौत को गंभीर बताते हुए साय सरकार पर सवाल खड़े किए।

कांग्रेस के इस दल में मोहला-मानपुर विधायक इंंदर साव मांडवी, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मांडवी, बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव और डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल पूर्व विधायक ममता



चंद्राकर शामिल रहे। दल ने गांव पहुंचकर मामले से जुड़े हालात की जानकारी ली और बच्चों की मौत के कारणों को लेकर चिंता जताई। दौरे के दौरान कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि पांचों बच्चों की मौत गंभीर कुपोषण के कारण हुई है।

उनका कहना था कि बैगा आदिवासी परिवारों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि जरूरतमंद

परिवारों को समय पर पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता, तो बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाए जा सकते थे।कांग्रेस दल के दौरे के बाद अब बच्चों की मौत के वास्तविक कारणों की जांच की मांग तेज होगी। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, कुपोषण की स्थिति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने रामचंडी मंदिर में पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की



महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत ग्राम गढफुलझर में बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सर्वप्रथम गढफुलझर स्थित रामचंडी मंदिर पहुंचकर मां रणेश्वर रामचंडी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां रामचंडी से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि, खुशहाली और निरंतर प्रगति के साथ प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद धर्मेन्द्र प्रधान, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक पुरेन्द्र मिश्रा, विधायक संपत अग्रवाल सहित बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज के पदाधिकारी, समाजजन एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय से सांसद धर्मेन्द्र प्रधान ने की शिष्टाचार भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं ओडिशा के संबलपुर से सांसद श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने श्री प्रधान का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।

झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में एनआई कार्य मेमू पैसेंजर ट्रेनों में आंशिक संशोधन

रायपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के मदेनजर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 68861/68862 गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर का संचालन निर्धारित अवधि में आंशिक संशोधन किया गया है। झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक 18 दिनों का प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य, 15 दिसंबर को 10 घंटे का नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य तथा 16 दिसंबर से 17 दिसंबर तक दो दिनों का पोस्ट-नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य निर्धारित है। उक्त कार्य के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा गाड़ी संख्या 68861/68862 को पूर्णतः निरस्त करने के बजाय आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 26 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक गाड़ी संख्या 68861 / 68862 (गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर) का परिचालन गोंदिया से बिलासपुर के बीच होगा। यह बिलासपुर से झारसुगुड़ा के मध्य रह रहेगी।

कालीबाड़ी मातृ एवं शिशु अस्पताल के तीन ऑपरेशन थिएटर का होगा उन्नयन



शिशु चिकित्सालय में तीन ऑपरेशन थिएटर को बेहतर बनाने का काम 16 नवंबर 2026 से शुरू होगा। इस काम को पूरा होने में लगभग तीन महीने लगेंगे। इस दौरान मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। उन्नयन कार्य के दौरान कालीबाड़ी अस्पताल में होने वाले ऑपरेशन जिला अस्पताल, पंडरी में किए जाएंगे। इसके लिए पंडरी अस्पताल में जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।ऑपरेशन थिएटर के उन्नयन के दौरान कालीबाड़ी अस्पताल में सामान्य प्रसव, ओपीडी और वार्ड की सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। मरीजों को इन सेवाओं के लिए अस्पताल में ही सुविधा मिलती रहेगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने 11 मेडिकल स्टोर्स का किया निरीक्षण

रायपुर। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला रायपुर की संयुक्त टीम ने आज जिले के 11 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य नशीले पदार्थों के रूप में दुरुपयोग की आशंका वाली औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय, अनधिकृत भंडारण और वितरण पर नियंत्रण के साथ औषधि संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना था।निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स में औषधियों के क्रय-विक्रय, उपलब्ध स्टॉक, भंडारण व्यवस्था और संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। टीम ने यह भी देखा कि औषधियों की खरीदी अधिकृत स्रोतों से हो रही है या नहीं तथा क्रय-विक्रय नशीले पदार्थों का रिकॉर्ड निर्धारित नियमों के अनुरूप रखा जा रहा है या नहीं। जांच में सर मेडिकल्स, भनपुरी; श्री राम मेडिकल स्टोर्स, कोटा; लक्ष्मी मेडिकल शॉप, संतोषी नगर; और मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, कुकुरबेड़ा में औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों के संधारण में अनियमितताएं पाई गईं।

राजधानी/छत्तीसगढ़

वोट चोरी पर सांसद संतोष पांडेय ने कहा- कांग्रेस भटका रही लोगों का ध्यान

■भूपेश ने 25 लाख नाम काटे जाने पर मांगा जवाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। भाजपा सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय ने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर को घेरते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष मतदाताओं को भ्रमित कर रहा है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने एसआईआर के दौरान 25 लाख लोगों के नाम काटे जाने का दावा करते हुए भाजपा और निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे हैं। दोनों नेताओं के बयानों के बीच प्रदेश में मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

संतोष पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के कामों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। उनके मुताबिक, कांग्रेस का वोट शेयर लगातार गिर रहा है और पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं के

मन में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है।

भाजपा सांसद ने निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष संस्था बताते हुए कहा कि वह जनादेश का रक्षक है। उन्होंने स्क्रूक की प्रक्रिया का बचाव करते हुए दावा किया कि केरल के कुछ कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसका समर्थन किया है।

पांडेय का कहना था कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में किसी तरह की गलती होने पर उसे सुधारने की व्यवस्था मौजूद है। इसके लिए संबंधित फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ताकि गलतियों को ठीक किया जा सके।

बिरागं नगर निगम में एसआईआर के दौरान बड़ी गड़बड़ी होने की बात सामने आने के संदर्भ में भी संतोष पांडेय ने प्रक्रिया में सुधार की व्यवस्था का जिक्र किया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उन्होंने बिरगांव मामले में गड़बड़ी की प्रकृति या प्रभावित मतदाताओं की संख्या का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया।

संतोष पांडेय ने महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप



लगाया कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती है। राष्ट्रपति की मिमिक्री से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उनका ध्यान इस मुद्दे की ओर नहीं जाता।

भाजपा सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी हमला बोला। पांडेय ने आरोप लगाया कि बघेल मनगढ़ंत बातें करते हैं। उन्होंने बघेल के परिवार के सदस्यों के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए सनातन धर्म, माता सीता और सगुण-निर्गुण से जुड़े विचारों पर सवाल उठाए।

दूसरी ओर, भूपेश बघेल ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर के दौरान 25 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे

गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी सूची सार्वजनिक की गई है या नहीं।

बघेल ने कहा कि संतोष पांडेय भाजपा के प्रवक्ता होने के साथ सांसद भी हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कथित बयान का भी हवाला दिया कि नाम 10 बार काटे जाएंगे। बघेल ने इसे अपने आरोपों की पुष्टि के तौर पर पेश करते हुए कहा कि भाजपा की ओर से ही ऐसी बात कही जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा और निर्वाचन आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। उनका बयान मतदाता सूची में नामों को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ दौर के लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि इससे भाजपा के बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

सिलेंडर मिलने की बात करती थीं, लेकिन अब अडानी गैस पाइपलाइन बिछाने जा रहे हैं।

बघेल ने आशंका जताई कि पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति बढ़ने से गैस एजेंसी संचालकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने मोबाइल रिचार्ज की कीमतों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह जियो का रिचार्ज प्लान महंगा हुआ है, उसी तरह गैस सिलेंडर भी और महंगा हो सकता है।

स्मृति ईरानी के स्वागत में पोस्टर और बैनर नहीं लगाने के निर्देश को लेकर भी भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पोस्टर-बैनर पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है और प्रधानमंत्री के करीब दिखने के लिए इस तरह के प्रचार पर खर्च किया जाता है।

बघेल ने कहा कि अब स्मृति ईरानी के दौरे पर पोस्टर-बैनर नहीं लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इससे भाजपा के बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

दीपक बैज ने भाजपा पर बस्तर दशहरा को मजाक बनाने का लगाया आरोप

■कहा- रीति-रिवाजों और परंपराओं से हुई छेड़छाड़

रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे और बस्तर दशहरा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार को मजाक बनाने, रीती-रिवाजों और परंपराओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी सवाल किया कि राष्ट्रपति 2 बार आई हैं, इससे क्या फायदा हुआ ?

उनका कहना है कि बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार को बीजेपी ने मजाक बना दिया है। 2 बार राष्ट्रपति आई हैं, इससे क्या फायदा हुआ ?, उन्होंने बस्तर दशहरा के रीती रिवाजों और परंपराओं के साथ छेड़छाड़ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि हद तो तब हुई जब बस्तर दशहरा का छया चित्र गलत दर्शाया गया, क्योंकि बस्तर में नक्सलियों के नाम से 4000



से ज्यादा नक्सली जेल में बंद है। बड़े दुर्दांत नक्सली सरकार के गोद में बैठे हैं। राष्ट्रपति के पास ताकत है वो उन्हें रिहा कर सकती है।

इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और 'वोट चोरी' के मुद्दों को लेकर दिल्ली में परंपराओं के साथ छेड़छाड़ होने का इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में कांग्रेसी शामिल होंगे।

दीपक बैज ने कहा कि 1 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी शामिल होंगे। वोट चोरी और एसआईआर के माध्यम से वोट काटे जाने के मुद्दे पर यह रैली आयोजित होगी। साथ ही ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर भी बड़ा प्रदर्शन होगा।

इसी के साथ ही दीपक बैज ने

भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दौरे पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल क्या स्मृति ईरानी बीजेपी की गुटबाजी को कम कर पाएंगी? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। क्या 'महंगाई कम होगी?' 13 रूप किलो में शकर मिलेगा? 400 रूपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, यह हमारा सवाल है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी की वो ख़ास है बड़ी नेता है उम्मीद है यह सब होगा।

भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति व सह प्रभारी सिद्धार्थ का 25 व 26 को छत्तीसगढ़ प्रवास

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी और राष्ट्रीय मंत्री व छत्तीसगढ़ प्रदेश सह-प्रभारी सिद्धार्थ शम्भू 25 अक्टूबर को दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान श्रीमती इरानी व श्री शम्भू भाजपा के पूर्व व वर्तमान पदाधिकारियों, पूर्व व वर्तमान सांसदों-विधायकों सहित निगम, आयोग व मण्डलों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों से संवाद स्थापित करेंगे।

भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीमती इरानी व सह प्रभारी शम्भू राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद 25 अक्टूबर (रविवार – प्रथम दिवस) को पूर्वाह्न 11 बजे से 11:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण करेंगे। इसके पश्चात पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री (संगठन) एवं प्रदेश महामंत्रियों के साथ संगठनात्मक बैठक आयोजित होगी। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ समीक्षा एवं रणनीतिक बैठक होगी। दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक सभी सम्भाग प्रभारी, सह-प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला



सह-प्रभारी तथा जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक सम्पन्न होगी। दोपहर 3:30 बजे से सायं 5 बजे तक पूर्व जनप्रतिनिधियों (पूर्व विधायकों एवं पूर्व सांसदों) के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। सायं 5:30 बजे से 7 बजे तक पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। सायं 7 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी।

भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीमती इरानी व सह प्रभारी श्री शम्भू अगले दिन 26 अक्टूबर (सोमवार – द्वितीय दिवस) को प्रातः 10 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक राज्य के सभी भाजपा विधायकों के साथ संगठनात्मक चर्चा एवं बैठक करेंगे। पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रदेश के पार्टी सांसदों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा।

दवाएं सस्ती हों, ग्रामीणों तक पहुंचे इलाज : डेका

■ एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि सस्ता इलाज, किरायाती दवाएं और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना देश की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इनके समाधान के लिए चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा को केवल कारोबार नहीं, बल्कि समाजसेवा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने नकली दवाओं पर रोक लगाने, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर वैज्ञानिक शोध करने और छत्तीसगढ़ की वनौषधियों के पारंपरिक ज्ञान को सामने लाने पर जोर दिया।

राज्यपाल श्री डेका आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया (एपीटीआई) के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 को संबोधित कर रहे थे। अधिवेशन का विषय फार्मा शिक्षक आत्मनिर्भर भारत के लिए फार्मासिस्ट तैयार करने का संकल्प था। राज्यपाल ने कहा कि देश ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण आबादी तक बुनियादी



सुविधाएं पहुंचाना अब भी चुनौती है। दवाओं की कीमत आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। चिकित्सकों को दवाएं लिखते समय मरीज की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और जहां संभव हो, कम कीमत वाली प्रभावी दवाओं के विकल्प अपनाने चाहिए।

उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि चिकित्सकों और फार्मासिस्टों को गांवों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करना होगा। गर्भवती महिलाओं, माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर बैगा समुदाय के पास औषधीय पौधों और पारंपरिक उपचार पद्धतियों से जुड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन और दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परंपराओं में उपलब्ध जानकारी की आधुनिक शोध के माध्यम से जांच कर उनकी उपयोगिता का आकलन करना जरूरी है। नकली दवाओं को गंभीर खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे

मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन पर संकट पैदा होता है तथा चिकित्सा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। फार्मसी के विद्यार्थियों, शिक्षकों और दवा उद्योग को

दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट का उपयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए करने तथा मौलिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों को महत्व देने की अपील की।

फार्मसी कार्डिसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. मोंटू एम. पटेल ने बताया कि बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप फार्मसी पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मेडिकल डिवाइस जैसे विषय शामिल किए गए हैं। उन्होंने अनावश्यक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के 42 स्थानों पर चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी।

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला ने विश्वविद्यालय में चल रहे शोध कार्यों का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ के वन आधारित औषधीय संसाधनों से नए उत्पाद विकसित करने और फार्मसी शोध को अन्य विज्ञान विषयों से जोड़ने की जरूरत बताई।

राज्योत्सव में दिखेगा सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो का रोमांच, कलेक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर स्थित सेंध लेक क्षेत्र में आयोजित होने वाले सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभाकक्ष में आयोजित बैठक में भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिला प्रशासन, नगर निगम तथा विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एयर शो के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं और दर्शकों की सुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने, यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने तथा दर्शकों एवं अतिथियों की सुविधा के लिए

आवश्यक प्रबंध करने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं, परिवहन व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही ड्रॉप जोन की लेबलिंग, आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं आवागमन की व्यवस्था तथा किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम समय पर सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की गई।

एयर शो के सफल संचालन के लिए आयोजन स्थल पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसमें विद्युत आपूर्ति, सॉफ्ट ग्राउंड, मेटेनैंग, मोबाइल टॉलेट, कार्यालयीन कार्यों के लिए आवश्यक स्थान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था शामिल रही। अधिकारियों ने आयोजन स्थल की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की



असुविधा से बचने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने पर चर्चा की।

बैठक में अतिथियों के आगमन एवं स्वागत, परिवहन और पार्किंग की समुचित व्यवस्था तथा एयर शो के व्यापक प्रचार-प्रसार से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई। आयोजन में शामिल होने वाले अतिथियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध करने पर बल दिया गया।

साथ ही आयोजन स्थल पर चिकित्सा सहायता एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संबंधित टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के महत्व पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सारंग

हेलीकॉप्टर एयर शो जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन, विद्युत आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित तैयारियों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। आयोजन के दौरान आम

नागरिकों एवं दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाओं की व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाला सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण होगा। इसे देखते हुए आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की नियमित समीक्षा, विभागীয় जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन और समय पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में नगर निगम रायपुर के आयुक्त संजित मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिस्वर्जन, भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए), परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

चुनाव आयोग को घरेने चले थे एसवाई कुरैशी

नीरज कुमार दुबे

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी इन दिनों चुनाव आयोग और मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर उनकी भिड़ंत पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्लल से हो गई है। कंवल सिब्लल ने कुरैशी के हमलावर रुख पर सवाल उठाते हुए इसे व्यक्तिगत रंजिश जैसा बताया है। वहीं इस टकराव ने कुरैशी को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि जिस चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और मजबूती का कभी कुरैशी खुद बचाव करते थे, आज उसी संस्था पर उनके लगातार हमलों के पीछे आखिर वजह क्या है ? हम आपको याद दिला दें कि जुलाई 2026 में एक साक्षात्कार के दौरान कुरैशी ने अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा था कि तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान चुनाव आयोग पर कोई दबाव नहीं था। उन्होंने आयोग की स्वतंत्रता और साख का जिक्र करते हुए कहा था कि उसकी स्थिति ऐसी थी कि कोई उस पर दबाव डालने की हिम्मत नहीं करता था और चुनाव की तारीखों की जानकारी भी सरकार को घोषणा के समय ही मिलती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और मजबूती को केवल कुरैशी के कार्यकाल से जोड़कर देखा जाना चाहिए? आयोग आज भी एक संवैधानिक संस्था है और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर अलग अलग उपाय जा रहे सवालों का जवाब तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर दिया जाना चाहिए, न कि लगातार आरोप लगाकर उसकी साख पर संदेह पैदा करके। आखिर कुरैशी जिस संस्थागत स्वतंत्रता को कभी अपनी उपलब्धि बताते थे, आज उसी संस्था के प्रति उनका रवैया किस आधार पर बदल गया है ? कंवल सिब्लल ने इसी बिंदु पर कुरैशी को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगातार हमलावर हैं और उनका रवैया व्यक्तिगत हिसाब-किताब चुकाने जैसा लगता है। सिब्लल ने साफ कहा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है, तब अपनी तरफ से अंतिम निष्कर्ष निकालकर उसे प्रचारित करना उचित नहीं है। उन्होंने कुरैशी को आगाह किया कि ऐसा करके वह अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिब्लल ने लिखा है कि उनका मकसद ट्रोлинг नहीं, बल्कि भारतीय चुनाव व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश पर सवाल उठाना है। लेकिन कुरैशी ने जवाब में मुद्दे का सामना करने के बजाय ट्रोлинг का कार्ड खेल दिया। उन्होंने तर्ज कसते हुए कहा कि वह वर्षों से दो रुपये वाले ट्रोल्स का सामना कर रहे हैं, तो क्या अब किसी पूर्व विदेश सचिव की ट्रोलिंग को विशेष सम्मान समझें ? यहां सवाल यह है कि क्या किसी वरिष्ठ राजनयिक की आलोचना को ट्रोलिंग बताकर खारिज कर देना पर्याप्त जवाब है ? देखा जाये तो कंवल सिब्लल ने उनके तर्कों पर सवाल उठाए थे, लेकिन कुरैशी ने बहस को व्यक्तिगत कटाक्ष की दिशा में मोड़ दिया। हम आपको यह भी बता दें कि सोशल मीडिया पर कुरैशी को घेरने वाले यूजर्स ने एक और असहज सवाल उठाया है। एक यूजर ने लिखा है कि जब वह खुद मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर जैसी कवायद क्यों नहीं हुई ? क्या मतदाता सूची को साफ-सुथरा रखना जरूरी नहीं था ? क्या मृत, स्थानांतरित और अन्य अयोग्य श्रेणियों में आने वाले नामों की जांच नहीं होनी चाहिए ? और क्या मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों को शामिल करने की कानूनी शर्त का पालन नहीं होना चाहिए ? देखा जाये तो ये सवाल अपने आप में विचाराणीय हैं। मतदाता सूची की शुद्धता और किसी पात्र नागरिक का वोट न छिनना, दोनों ही चुनावी व्यवस्था की बुनियादी जरूरतें हैं।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

20-सर्वास्तित्वाद (वैभाषिक)

गताक्त से आगे...

इसलिए दूसरे बौद्ध सम्प्रदायों ने, विशेषकर प्राचीन थेरावाद ने, सर्वास्तित्वाद के इस सिद्धान्त का विरोध किया। परन्तु सर्वास्तित्वाद ने इस दोष का समाधान यह दिया कि हम धर्मस्वभाव को तीनों कालों में रहने वाला होने पर भी नित्य नहीं मानते, क्योंकि नित्यता का अर्थ है कि परिवर्तन का अभाव, परन्तु धर्म स्वभाव भविष्य में किसी धर्म के बाह्य दृश्यमान अस्तित्व की सम्भावना का द्योतक है और उसी प्रकार भूतकाल के अस्तित्व का भी द्योतक है। यह वर्तमान काल में आने की सम्भावना तीनों कालों में अर्थात् सर्वदा रहती है।

इस प्रकार सर्वास्तित्वाद का अर्थ है कि सर्वदास्तित्वाद, न कि सब पदार्थों के अस्तित्व का बाद, अर्थात् बाह्यार्थवाद । और क्योंकि यह दृश्य बाह्यरूप में प्रकट होने की सम्भावना तीनों कालों में विद्यमान होने पर भी स्थिरता या नित्यता को द्योतित

नहीं करती प्रत्युत परिवर्तन को ही द्योतित करती है। इसलिए धर्मस्वभाव तीनों कालों में रहनेवाला होने पर भी नित्य नहीं कहा जा सकता।

सर्वास्तित्वाद का यह सिद्धान्त और उसका उपयुक्त समाधान बौद्धधर्म के सामान्य क्षणिक सिद्धान्त से कहां तक संगत हो सकता है, यह प्रश्न बना ही रहता है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक धर्म को क्षणिक मानकर भी मानवस्वभाव में साधारणतया प्रत्येक वस्तु को भूत और भविष्य में भी सोचने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी का यथाकथञ्चित् समाधान सर्वास्तित्वादी वैभाषिकों ने किया था ।

कई बार सर्वास्तित्वाद का बाह्यार्थवाद के रूप में समझ कर, जैसा कि शङ्कराचार्य आदि ने समझा था, सौत्रान्तिकों को भी सर्वास्तित्वादी समझ लिया जाता है।

क्रमशः...



ज्ञान/मीमांसा

मोदी मॉडल पर चुनाव लड़ने चले थे डोनाल्ड ट्रंप?

अभिनय आकाश

अमेरिका में 3 नवंबर को मिड टर्म चुनाव होने हैं और इन चुनाव से यह तय होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस के दोनों सदनों में आप अपना बहुमत बचा पाती है या फिर नहीं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सामने आए कई सर्वेक्षणों यानी कि सर्वे में रिपब्लिकन पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इन सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी मतदाता अब अर्थव्यवस्था, महंगाई और सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का मानना है ट्रंप की नीतियों की वजह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और ज्यादा महंगी हो गई है यानी महंगाई बढ़ी है। ऐसे में सवाल है क्या अमेरिका की जनता ट्रंप सरकार के कामकाज से नाराज है ? क्या यह नाराजगी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को भारी पड़ सकती है ? और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती है तो ट्रंप के लिए आगे की राह फिक्ती मुश्किल हो जाएगी ?

आपने देखा होगा किस तरीके से अमेरिका ने रशिया से डीजल खरीदने की डील की वो कोई आम डील नहीं थी। वो डीजल जरूर आम हो सकता है। 3 लाख टन डीजल जरूर आम सी बात हो सकती है। जरूर किसी और देश से ज्यादा पैसे में अमेरिका खरीद सकता था उस डीजल को लेकिन रशिया के सामने ही क्यों इसके लिए गिड़गिड़ाया ? क्यों यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया ? जिस यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर दिए कि रूस के साथ लड़ाई करो। मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसे जापान का साथ छोड़ दिया। साउथ कोरिया को मना कर दिया। यूक्रेन का नेट बंद करवा दिया। आइलॉन मस्क के यूरोप का नेट की स्पीड घटवा दी। डेनमार्क को धमका दिया कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। वो ट्रंप आज दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। दुनिया में भी पहले रूस के सामने गिड़गिड़ाए और अब भारत में उनका संदेश लेकर मार्को रूबियो फिलहाल भारत में मौजूद है। मार्को रूबियो जामनार रिफाइनरी में गए। जामनार की रिफाइनरी वो रिफाइनरी है जो रोजाना 14 लाख बैरल तेल रिफाइन करती है। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा तो अमेरिका ने कर लिया लेकिन उसे रिफाइन नहीं कर सकता। उसके लिए भारत की जरूरत होगी। आज अमेरिका को डीजल की जरूरत है। पेट्रोल की जरूरत है और इसी वजह से जो



अफ्फवल रेंटिंग है ट्रंप की वो लगातार घटती जा रही है क्योंकि अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ रही है। अमेरिका में रहना मुश्किल हो गया है। अमेरिका में रहना महंगा हो गया है। खाना महंगा हो गया है। ऊर्जा महंगी हो गई है। तो अब विटर्म में जाने वाले हैं ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। दोनों पार्टियां चुनाव में जाने वाली हैं। 3 नवंबर को यह चुनाव है। ट्रंप चाहते हैं कि 3 नवंबर से पहले लगभग 10-12 दिन जो हैं उससे पहले पहले वो सब कुछ ठीक कर लें। जो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है उसे वो कंट्रोल कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स दावा करती है कि अमेरिका में रहने वाले चार लोगों में से तीन लोग ट्रंप से नफरत करते हैं। ट्रंप की नीतियों का समर्थन नहीं करते। मतलब 25ब लेकिन कुछ रिपोर्ट्स फिर भी थोड़ा सा दावा करती हैं कि नहीं थोड़ी सी इज्जत बची हुई है और अभी लगभग 31ब तक ट्रंप की अफ्फवल रेंटिंग है। मीडियाकोर्स देखें

आपको बता दें कि अफ्फवल रेंटिंग जो होती है वो डोनाल्ड ट्रंप की गिरती जा रही है। अब अफ्फवल रेंटिंग का मतलब यह होता है किनेने लोग राष्ट्रपति के कामकाज से संतुष्ट हैं और कितने लोग उनसे असहमत हैं। एनबीसी न्यूज़ के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 34 प्रतिशत अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से संतुष्ट हैं। जबकि 66 प्रतिशत लोगों ने उनके प्रदर्शन पर असहमति जताई है। इस सर्वेक्षण में 51 प्रतिशत लोगों ने तो ट्रंप के कामकाज से बहुत ज्यादा असहमति जताई है और यह उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान इस सर्वे में दर्ज किया जा किया गया सबसे ऊंचा आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं वाशिंगटन पोस्ट एबीसी न्यूज़ और जो एम्पोस में सर्वे हुए हैं उसमें ट्रंप के अफ्फवल रेंटिंग सिर्फ 33 प्रतिशत सामने आई है। जबकि 66 प्रतिशत लोगों ने उनके कामकाज को लेकर असहमति जताई है। यह आंकड़ा भी इस

सर्वेक्षण के इतिहास में ट्रंप का सबसे कमजोर प्रदर्शन बताया गया। यानी कि सर्वे के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि ट्रंप को लेकर अमेरिकी मतदाताओं के बीच असंतोष बढ़ा है। महंगाई बनी ट्रंप की सरकार की सबसे पर बड़ी परेशानी ये लोगों का कहना है क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है किसी भी देश के लिए सरकार का चुनावी भविष्य तय करने के लिए ये बड़ी भूमिका भी

निभाता है और यह मुद्दा है अर्थव्यवस्था का।

हालांकि इसका मकसद ट्रंप के समर्थकों की भागीदारी बढ़ाना था। लेकिन इस कदम से डेमोक्रेट और निर्दलीय मतदाता भी उनकी मतलब जैसे उन्होंने कहा कि हर सीट पर आप ट्रंप को ही मानकर चलिए कि ट्रंप चुनाव लड़ रहे हैं। चाह तो ये चाहते थे कि रिपब्लिकन की जो वोट है वो बढ़े लेकिन यहां पर मामला उल्टा पड़ गया। उल्टा यहां पर अगर डेमोक्रेट्स की बात करें तो उनका कहना है कि ट्रंप ने खर्च कम करने और युद्ध खत्म करने के अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने वादा किया कि अगर मतदाता उन्हें किसी भी सदन में बहुमत देते हैं तो वो अमेरिकियों के जीवन यापन का खर्च कम करने के लिए काम करेंगे और कथित भ्रष्टाचार के लिए प्रशासन को जवाबदेह ठहराएंगे। यहां पर अगर आपको बात करें तो ऊर्जा जो है वो 34 प्रतिशत तक महंगी हो चुकी है। खाना पीना ढाई से तीन गुना तक ढाई से 3 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है। यहां पर ये अमेरिका के हाल हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो ट्रिपल ए के अनुसार पेट्रोल की राष्ट्रीय औसत कीमत 4.28 डॉलर है जो 1 साल पहले की तुलना में 1.2 डॉलर ज्यादा है। मतलब 5 प्रति गैलन तक यहां पर कीमत बढ़ चुकी है। डीजल की कीमतें लगभग 3 गैलन 3 डॉलर प्रति गैलन तक यहां पर बढ़ चुकी हैं। और अगर बाकी बात करें तो गृह सुरक्षा विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि जो बाइडन के प्रशासन की तुलना में दक्षिणी पश्चिमी सीमा में पकड़े गए जो प्रवासी आते हैं उनमें कमी आई है। 95 प्रतिशत तक उनका आना कम हुआ है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो यहां पर महंगी हुई हैं। अमेरिका में रहना महंगा हो चुका है। मतलब एक रिपोर्ट यह दावा करती है कि अगर किसी परिवार का खर्च महीने का अमेरिका में रहने का अब तक 3000 डॉलर था

तो वो अब यहां मतलब अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो वो 311 डॉलर तक पहुंच चुका है। मतलब 11 डॉलर की बढ़ोतरी पिछले कुछ महीनों में हुई है। जिस तरीके से ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज चौक की हुई है और बाबल मंदिर पर कब्जा किसका है ?

हृतियों का कब्जा है। हृतियों को हथियार कौन दे रहा है ? चीन और रूस दे रहे हैं। ईरान को हथियार कौन दे रहा है ? चीन और रूस दे रहे हैं। ईरान का तेल कौन खरीद रहा है ? चीन खरीद रहा है। मतलब एक तरीके से अमेरिका को पूरी तरीके से रशिया और चाइना ने काउंटर कर लिया है। घेर कर मार दिया है। अब यहां जीत तो बहुत दूर की बात है। हार भी बहुत बुरी ना ट्रंप की हो जाए। ये कहा जा रहा है अमेरिका में। जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जो रेंटिंग है या फिर जो उनका आंकड़ा है जिस तरीके से भी अमेरिका में ये गिनती होती होगी वो 92 प्रतिशत 52 प्रतिशत के पार पहुंच चुका है। वहीं ट्रंप की पार्टी की बात करें तो 42 फीसदी पर अटक हुई है। और अगर ये अफ्फवल रेंटिंग नहीं बढ़ी तो फिर रिपब्लिकनंस चुनाव हार जाएंगे और राष्ट्रपति तो रहेंगे। ट्रंप 4 साल तक आने वाले 2 साल भी राष्ट्रपति तो रहेंगे। लेकिन काम क्या कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वह वक्त बताएगा। योजनाएंखोजें

रिपब्लिकन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह मतदाताओं को कैसे भरोसा दिलाएं कि उनकी नीतियां अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को सर्वेक्षणों में बढ़त मिलती दिखाई दी है। देखिए चुनावी मुकाबले की बात करें तो सर्वे में डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से आगे दिख रही है। एबीसी न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट और कई ऐसे अमेरिकी जो चैनल्स हैं उसके सर्वे में प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को 52 प्रतिशत और रिपब्लिकन उम्मीदवारों को 44 प्रतिशत समर्थन मिला। यानी डेमोक्रेट्स को 8 प्रतिशत अंकों की बढ़त दिखाई दी। वहीं रटर्स और अह इम्पोस के सर्वेक्षण में डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिली। इस सर्वेक्षण में डेमोक्रेट्स को 47 और रिपब्लिकन पार्टी को 35 प्रतिशत समर्थन मिला। यानी कि यहां भी अंतर 12 प्रतिशत अंकों का है। इन आंकड़ों से पता चलता है चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रदर्शन बेहतर दिखाई दे रहा है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आधार पर सीधे चुनाव के नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

साहिर लुधियानवी

प्रीतम से प्यार कर बैदे,
लेकिन अमृता के घरवालों
को यह पसंद नहीं आया,
क्योंकि साहिर एक मुस्लिम थे
और दूसरी और गरीब थीं।
अमृता के पिता के कहने पर साहिर को कॉलेज से निकाल दिया गया।
आज भी अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी के प्यार के किस्से बड़ी दिलचस्पी से सुने जाते हैं।
हालांकि दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हो सका।

साहिर लुधियानवी के जीविका चलाने के लिए तरह-तरह की छोटी-मोटी नौकरियां कीं।
साल 1942 में वह लाहौर आ गए और इसी साल उन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह ‘तरिक्षया’ छपावाई।
जिसके बाद उनको शोहरत मिलना शुरू हो



लुधियानवी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया।

इसके बाद साहिर कुछ समय दिल्ली में रहे और फिर मुंबई आ गए।
यहां पर उन्होंने बतौर लिंरिसिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया।
बतौर कवि उनकी इतनी कमाई नहीं होती थी, जितनी कि इंडस्ट्री में गाने लिखने के बाद होने लगी थी।
साल 1948 में उन्होंने %आजादी की

राह पर% में चार गांों के साथ इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की।
इसके बाद साहिर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।
साल 1951 में नौजवान से एसडी बर्मन के साथ साहिर लुधियानवी को पहचान मिली।

बाजी से साहिर लुधियानवी को खूब सफलता मिली।
इस दौरान साहिर को गुरुदत्त की टीम का हिस्सा माना जाता था।
साहिर की एसडी बर्मन के साथ आर्नौतियों फिल्म प्यासा थी।
जोकि साल 1957 में आई थी।
इस फिल्म में गुरुदत्त ने विजय नाम के कवि का किरदार निभाया था।
इस फिल्म के बाद साहिर लुधियानवी और एसडी बर्मन में आर्टिस्टिक और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मतभेद हुआ और दोनों अलग हो गए।

वहीं 25 अक्तूबर 1980 को साहिर लुधियानवी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था।

वैश्विक सहयोग की नई दिशा तय करेगा 12वाँ ब्रिक्स

विनोद सिंह ‘तकियावाला’

वैश्विक राजनीति, आर्थिक सहयोग और तकनीकी परिवर्तन के मौजूदा दौर में संसदों की भूमिका केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं रह गई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति, विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान में संसदीय संवाद का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में भारत की अध्यक्षता में 26 और 27 अक्तूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला 12वाँ ब्रिक्स संसदीय मंच विशेष महत्व रखता है। संसद भवन परिसर स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के संसदीय नेता जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाने के विषय पर विचार-विमर्श करेंगे।

सम्मेलन का उद्घाटन 26 अक्तूबर को होगा और इसका समापन 27 अक्तूबर को किया जाएगा। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 22 अक्तूबर को संसद भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में सम्मेलन की रूपरेखा और प्रमुख विषयों की जानकारी देते हुए इसे भारत के संसदीय राजनय के इतिहास में एक नया अध्याय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे और आगंतुक शिष्टमंडलों के नेताओं से भेंट करेंगे। सम्मेलन में विभिन्न देशों के पीठासीन अधिकारियों, संसदीय नेताओं, संसद सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी से लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संवाद को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश तथा राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों की सहभागिता भी प्रस्तावित है।

ब्रिक्स संसदीय मंच का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह विभिन्न देशों की संसदों को साझा चुनौतियों पर विचार करने, अनुभवों का आदान-प्रदान करने और सहयोग की संभावनाएँ तलाशने का अवसर प्रदान करता है। भारत की मेजबानी में होने



वाला यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है, जब दुनिया तकनीकी क्रांति, आर्थिक अनिश्चितताओं, पर्यावरणीय चुनौतियों और वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक बनाने की आवश्यकता जैसे अनेक प्रश्नों से जुड़ा रही है। इन परिस्थितियों में संसदों के बीच नियमित संवाद केवल औपचारिक कूटनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करने का माध्यम भी बन सकता है।

12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मुख्य विषय ‘जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना’ अपने आप में व्यापक अर्थ रखता है। विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उसका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुँचे और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे। आर्थिक प्रगति के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सुविधाओं और समान अवसरों की उपलब्धता भी विकास की कसौटी है। इस प्रक्रिया में संसदों की जिम्मेदारी सकारां पर विचार-विमर्श करने, कानून बनाने, नीतियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और जनहित के प्रश्नों को लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र में रखने की है।

संसद जनता की आकांक्षाओं और शासन व्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण सेतु होती है। विभिन्न देशों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की आकांक्षा एक साझा उद्देश्य है। इसलिए संसदीय मंच पर जन-केंद्रित विकास के विषय पर होने वाली चर्चा का

महत्व केवल सदस्य देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके माध्यम से यह समझने का अवसर मिलेगा कि बदलती परिस्थितियों में संसदें किस प्रकार अपनी संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को अधिक प्रभावी बना सकती हैं।

संस्थागत सुदृढ़ता से लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती ->सम्मेलन के पहले उच्चस्तरीय सत्र में बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में संसदों की भूमिका पर विचार किया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता उसके संस्थागत ढाँचे, नियमों के पालन, जवाबदेही और नागरिकों के विश्वास पर निर्भर करती है। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि उसकी संस्थाएँ बदलती चुनौतियों के बीच अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें।

संसदों के सामने आज नीतिगत जटिलताओं, तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने की चुनौती है। ऐसी स्थिति में संसदीय प्रक्रियाओं की गुणवत्ता, जनप्रतिनिधियों की क्षमता और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न देशों के अनुभवों का आदान-प्रदान इन चुनौतियों से निपटने के व्यावहारिक उपाय तलाशने में सहायक हो सकता है। संस्थागत सुदृढ़ता का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यवस्थागत सुधार नहीं, बल्कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही और जनविश्वास को मजबूत करना भी है।

12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का दूसरा प्रमुख सत्र नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के मानव-केंद्रित उपयोग पर केंद्रित होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक ने शासन, संचार, सूचना के आदान-प्रदान तथा सार्वजनिक सेवाओं के स्वरूप में परिवर्तन की व्यापक संभावनाएँ पैदा की हैं। इन तकनीकों का उपयोग प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सूचनाओं तक पहुँच बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

सकता है।

हालाँकि, तकनीकी प्रगति के साथ डेटा की सुरक्षा, निजता, पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक के जिम्मेदार उपयोग से जुड़े प्रश्न भी सामने आते हैं। संसदों की भूमिका इन सवालों और चुनौतियों के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। कानून और नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ नागरिकों के अधिकारों तथा सार्वजनिक हितों की रक्षा भी करें।भारत में डिजिटल परिवर्तन के बढ़ते महत्व को देखते हुए इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय संसदीय विमर्श विशेष प्रासंगिकता रखता है। अलग-अलग देशों के अनुभवों से यह समझने में मदद मिल सकती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किस प्रकार जनहित में किया जाए और तकनीकी विकास के लाभ व्यापक समाज तक कैसे पहुँचाए जाएँ। मानव-केंद्रित नवाचार का आशय यही है कि तकनीक का मूल्यांकन केवल उसकी क्षमता से नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में उसके वास्तविक योगदान से भी किया जाए।

वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता ->सम्मेलन के तीसरे सत्र में संसदीय सहयोग के माध्यम से अधिक प्रतिनिधिक वैश्विक शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा। वर्तमान विश्व व्यवस्था में अनेक ऐसे विषय हैं, जिनका प्रभाव किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। आर्थिक सहयोग, तकनीकी बदलाव, पर्यावरणीय संकट और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यक्षमता जैसे प्रश्नों पर व्यापक संवाद की आवश्यकता है। ऐसे विषयों पर किसी एक देश के प्रयासों के साथ-साथ देशों के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण होता है।वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक बनाने का प्रश्न इस बात से जुड़ा है कि अंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न देशों की आवाज और उनके हितों को किस प्रकार प्रभावी स्थान मिले। ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंच इस संदर्भ में विचारों के आदान-प्रदान और नागरिकों का बेहतर प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

आज का इतिहास

- 1296 संत ज्ञानेश्वर का निधन हुआ।
- 1415 इंग्लैंड ने उत्तरी फ्रांस में एंजिनकोर्ट की लड़ाई जीती थी।
- 1760 जॉर्ज तृतीय ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राजा बने।
- 1812 युद्ध के दौरान अमेरिका फ़िगोट यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रिटिश पोत मैसिडोनिया पर कब्जा कर लिया था।
- 1870 अमेरिका में पहली बार पोस्टकार्ड का इस्तेमाल किया गया।
- 1917 बोल्शेविक (कम्युनिस्टों) व्लादिमीर इलिच लेनिन ने रूस में सत्ता हथिया ली थी।
- 1924 ब्रिटिश अधिकारियों ने सुभाषचंद्र बोस को गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल भेजा था।
- 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में चीन ने ताइवान पर कब्जा किया था।
- 1951 भारत में पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई थी।
- 1995 तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र के 50वें वर्षगांठ सत्र को संबोधित किया।
- 1955 पहली बार घरेलू इस्तेमाल के लिए माइक्रोवेव ओवन की ब्रिकी टप्पन कंपनी ने शुरू की।
- 1960 न्यूयॉर्क में पहली इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच बाजार में आई।
- 1962 अमेरिकी लेखक जॉन स्टीनबेक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
- 1964 अवादी कारखाने में पहले स्वदेशी टैंक विजयंत का निर्माण किया गया था।
- 1971 संयुक्त राष्ट्र महासभा में ताइवान को चीन में शामिल करने के लिए मतदान हुआ था।
- 1972 एफबीआई ने पहली बार महिला एजेंटों को काम पर रखा।
- 1995 प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र के 50वें वर्षगांठ सत्र को संबोधित किया था।
- 2000 अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 13 दिन के अभियान के बाद सकुशल वापस लाया गया था।
- 2005 ईराक में नये संविधान को जनमत संग्रह में बहुमत के साथ मंजूरी मिली थी।
- 2008 सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी को 6 माह की सज़ा सुनाई गई थी।
- 2009 बगदाद में बम धमाकों से 155 लोगों की मौत तथा 721 घायल हुए थे।
- 2012 क्यूबा और हैती में तूफान सैंडी से 65 लोगों की मौत तथा आठ करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था।
- 2013 राजजोरिया में सेना ने आतंकवादी संगठन बोको हराम के 74 आतंकवादियों को मार गिराया था।



नाना ने 5 साल तक नहीं की थी पिता जी से बात: **सलमान खान**

हाल ही में बॉलीवुड के दबंग भाईजान सलमान खान ने खुलासा किया कि उनके नाना उनकी मॉम और डैड की शादी के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने पापा सलीम खान से पूरे पाँच साल तक बात तक नहीं की थी। सलमान ने यह चौकाने वाला किस्सा किसी और जगह नहीं, बल्कि बिग बॉस 20 के मंच पर वीकेंड के वार के दौरान सबके सामने रखा। इतना ही नहीं, एक्टर ने अपने माता-पिता की लड़ाई को लेकर भी हैरान करने वाला खुलासा किया, जब सलमान की माँ, सलमा खान, सलीम खान संग बहस करके गुर्रसे में घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी। बिग बॉस 20 के स्टेज पर कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए सलमान खान ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा यह पुराना और दिलचस्प राज खोला। उन्होंने बताया कि जब उनके माता-पिता की शादी हुई थी, तब किसी धर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि असली वजह कुछ और ही थी। सलमान ने बताया कि उनके नाना इस बात से नाराज थे कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे गुड लुकिंग इंसान से हो रही है जो एक्टर बनना चाहता है और फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमा रहा है। नाना को इसी बात पर सबसे बड़ा एतराज था। सलमान ने आगे बात करते हुए बताया कि उनके नाना को हमेशा यही डर सताता रहता था कि उनकी बेटी इस फिल्मी माहौल में अपना जीवन कैसे बिताएगी। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने सलीम खान से पाँच साल तक दूरी बनाए रखी और बातचीत बंद कर दी थी। एक्टर ने यह भी साझा किया कि जब उनके छोटे भाई सोहेल खान का जन्म हुआ, तब उनके नाना माहिम से बांदा आए थे। वह अपने साथ जलेबी का डिब्बा लेकर आए थे और उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया था कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि उन्होंने अपने नाती-नातिन को बचपन में बड़े होते हुए नहीं देखा। वहीं, सलमान ने ये भी बताया कि एक बार जब डेड और मॉम की एक लड़ाई हुई तो मॉम गुर्रसे में मायके चली गई, लेकिन उनके नाना ने फिर उनकी माँ को कहा कि वह जब चाहें घर आ सकती हैं, लेकिन लड़ाई के बाद कभी नहीं। सलमान ने अपने नाना के शब्दों को दोहराते हुए कहा, उन्होंने कहा कि तुम कभी भी घर आ सकती हो, लेकिन झगड़ा करके तुम नहीं आओगी। यह एक ऐसी सीख थी जो सलमा खान के जीवन में हमेशा रही। सलीम खान और सलमा की प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों के प्यार की शुरुआत बालकनी से एक-दूसरे को देखने से हुई थी। सलीम खान ने खुद एक बार बताया था कि वे शाम और रात के वक्त लाइन में खड़े होकर एक-दूसरे से मिल लिया करते थे। जब सलमा के घर वालों को इस बात की भनक लगी, तो उन पर काफी दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद दोनों ने कड़ा कदम उठाते हुए शादी करने का फैसला किया। सलीम खान की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हेलेन से हुई। सलीम और हेलेन साल 1963 में एक फिल्म के सेट पर मिले थे, जहां से दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद सलीम और हेलेन ने साल 1980 में शादी कर ली। हालांकि सलीम खान पहले से शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे थे, लेकिन इसके बावजूद पूरे परिवार ने हेलेन को खुले दिल से अपनाया।



कबूतर में मुख्य भूमिका निभाएंगे **नवाजुद्दीन सिद्दीकी**

बॉलीवुड के लेखक-निर्देशक इशान शर्मा की पहली फीचर फिल्म कबूतर में बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस अनोखी फिल्म की मुख्य शूटिंग 2027 की शुरुआत में दिल्ली में शुरू होने वाली है, जो पुरानी दिल्ली की जर्जर होती इमारतों और वहां की अनूठी दुनिया की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी। कबूतर का निर्माण निखिल चौधरी की कंपनी एमडीसी फिल्मवर्क्स कर रही है। यह भारत, फ्रांस और नॉर्वे के बीच एक महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय सह-निर्माण है, जिसमें भारत की एमडीसी फिल्मवर्क्स, फ्रांस की हायकू फिल्म्स और नॉर्वे की रैन फिल्म शामिल हैं। भारतीय पक्ष से रोहित सक्सेना सह-निर्माता की भूमिका निभा रहे हैं। कबूतर की कहानी महबूब नाम के एक सड़कछाप जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी जिंदगी में अनोखे तरीके से काम करता है। महबूब गुप्त रूप से जिन्न के नाम लिखे गए खत पढ़ता है, ताकि संभावित ग्राहक तलाश सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात नाओको से होती है, जो जापान से आई एक पर्यटक है और अपने अतीत के दर्द से जूझ रही है। कहानी में रूबी नाम का एक छोटा बच्चा भी है, जो अपने माता-पिता की तलाश में है। फिल्म में अनोखेपन, भावनात्मक गहराई और मानवीय अनुभवों के विरोधाभासों को एक अलग अंदाज में पेश किए जाने की उम्मीद है, और इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने अभिनय का एक बिस्कुट नया पहलू दिखाते नजर आएंगे।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए चुने जाने पर निर्माता निखिल चौधरी ने कहा, नवाज असाधारण अभिनय क्षमता वाले कलाकार हैं। वह गैंग्स ऑफ वासेपुर में खतरनाक नजर आ सकते हैं, तो द लंचबॉक्स में उनका अभिनय दिल को छू लेने वाला और बेहद कोमल हो सकता है। वह उन चुनिंदा भारतीय अभिनेताओं में से हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत पहचान है। उनकी फिल्में कई बार कान फिल्म महोत्सव तक पहुंची हैं और उन्हें इंटरनेशनल एमी के लिए भी नामांकित किया गया है। भारत-फ्रांस-नॉर्वे के सह-निर्माण वाली फिल्म कबूतर को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिहाज से यह बेहद अहम है। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा, नवाज दिल्ली को गहराई से जानते हैं। इशान और मेरे लिए यह फिल्म इस शहर के प्रति प्रेम-पत्र की तरह है। हमें ऐसे अभिनेता की जरूरत थी, जो दिल्ली को समझ सके, उसे महसूस कर सके और अपने अभिनय में जीवंत कर सके। नवाज ये तीनों खूबियां रखते हैं। पिछले कई वर्षों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भारतीय सिनेमा के सबसे विशिष्ट अभिनेताओं में अपनी जगह बनाई है। जटिल, असामान्य और गहराई से मानवीय किरदारों को सहजता से निभाने की उनकी क्षमता ने उन्हें खास पहचान दिलाई है। उनकी चर्चित फिल्मों में अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर, रितेश बत्रा की द लंचबॉक्स और नंदिता दास की मंटो शामिल हैं।



उड़ता तीर मूवी रित्यू : आयुष्मान खुराना की कॉमेडी और कन्प्यूजन से भरपूर फिल्म, हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान का एक खुफिया एजेंट भारत में एक हादसे का शिकार हो जाता है और अपनी याददाश्त खो बैठता है। होश में आने पर उसे लगता है कि वह भारत का काउंटर-इंटेलिजेंस ऑफिसर है। बस, इसी गड़बड़ी से शुरू होता है फिल्म ‘उड़ता तीर’ का मजेदार सफर, जहां गलतफहमियां, उलझनें और हास्यास्पद हालात एक के बाद एक सामने आते हैं। आकाश ए. कोशिक के निर्देशन और लेखन में बनी यह फिल्म अपनी मजेदार कहानी, चुटीले डायलॉग और शानदार कॉमिक टाइमिंग के दम पर दर्शकों को हंसाने की कोशिश करती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी कई मौकों पर कॉमेडी का मजा बढ़ा देता है। ‘उड़ता तीर’ में जिस तरह की उलझनें दिखाई गई हैं, वे कई बार इतनी अजीब और मजेदार होती हैं कि हंसी अपने आप छूट जाती है। फिल्म के डायलॉग कहानी की जान हैं। कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग और एक-दूसरे के साथ उनकी केमिस्ट्री सीन को मजेदार बनाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सही समय पर कॉमेडी के साथ मेल मिलाता है और कई सीन का असर बढ़ा देता है।



अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने मनोज बाजपेयी के बयान का किया समर्थन - कहा - नकारात्मकता से हटकर सकारात्मक नजरिया अपनाने की जरूरत

बॉलीवुड की बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने हाल ही में अपने सह-कलाकार और वरिष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी के उस बयान का पूर्ण समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसके पेशे के आधार पर आंकना सही नहीं है। दिव्या दत्ता का मानना है कि समाज में हर क्षेत्र और पेशे में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मौजूद होते हैं, इसलिए कुछ व्यक्तियों की गलतियों के कारण पूरे विभाग या संस्था को कटघरे में खड़ा करना न्यायसंगत नहीं है। उनका यह बयान फिल्म उद्योग और आम जनता के बीच एक नई चर्चा को जन्म दे रहा है। हाल के दिनों में मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ के आवास के बाहर हुई गोलीबारी की घटना और दिल्ली-

मुंबई में पुलिस प्रशासन की आलोचना के संदर्भ में मनोज बाजपेयी ने निष्पक्ष दृष्टिकोण रखने की बात कही थी। उसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए दिव्या दत्ता ने कहा कि मनुष्य का स्वभाव अक्सर ऐसा होता है कि वह अच्छी और सकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर देता है और नकारात्मक चीजों की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक हम किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं जान लेते, तब तक केवल उसकी वर्दी या उसके पेशे को देखकर उसके चरित्र का फैसला करना अनुचित है। दिव्या दत्ता ने इस बात पर चिंता जताई कि आजकल लोग सकारात्मक पहलुओं को पीछे छोड़कर नकारात्मक खबरों को जल्दी पकड़ लेते हैं। उन्होंने

कहा कि पुलिस हो या कोई अन्य पेशा, उसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। ऐसे में कुछ काली भेड़ों की वजह से पूरे तंत्र पर सवाल उठाना उन लोगों के मनोबल को तोड़ता है जो दिन-रात निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए समाज को अपना नजरिया बदलने की सख्त जरूरत है। काम की बात करें तो दिव्या दत्ता और मनोज बाजपेयी के साथ फिल्म गजब रात में अभिनय करते नजर आईं। इस फिल्म को लेकर पहले काफी विवाद हुआ था और इसका शुरुआती शीर्षक घूसखोर पंडित रखा गया था, जिसे बाद में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए बदलकर गजब रात कर दिया गया। रितेश शाह के निर्देशन में बनी और प्रसिद्ध निर्माता नीरज



पांडे की कंपनी फाइव स्टोरीटेलर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है।

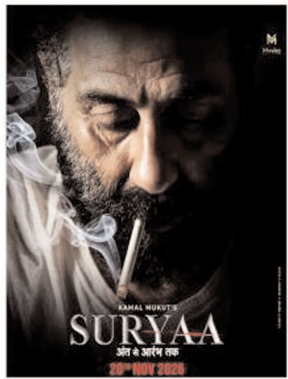
मैं हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हूं: **माही विज**

हाल ही में बिग बॉस-20 में अभिनेत्री माही विज से साथी प्रतियोगी काजी तौकीर ने उनकी प्रेम कहानी के बारे में मजाकिया अंदाज में सवाल पूछा, जिस पर माही विज शर्मा गईं। तौकीर ने पूछा कि क्या कोई भी व्यक्ति उनसे संपर्क कर सकता है। इस सवाल के जवाब में माही ने कहा, नहीं, कोई मुझसे संपर्क नहीं कर सकता। मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूं। उनके इस जवाब ने चर्चा को और हवा दी, खासकर ऐसे समय में जब उनके निजी जीवन को लेकर अटकलें तेज हैं। इसके बाद काजी ने माही से और जानकारी लेने की कोशिश की, यह जताते हुए कि शायद वह कुछ चुनिंदा लोगों में ही दिलचस्पी रखती हों। उन्होंने माही को चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या वह तीन-चार लोगों में से किसी को चुनेंगी या कोई उसे सीधे शादी का प्रस्ताव दे सकता है। काजी के लगातार मजाक उड़ाने पर माही मुस्कराती और शर्माती नजर आईं, लेकिन अपनी बात पर कायम रही। उन्होंने यह भी सवाल किया कि उनके पास कितने विकल्प हैं, यह इशारा करते हुए कि माही की प्रतिक्रिया से शायद यह पता चलता है कि उनकी जिंदगी में कोई खास है या उन्हें कई लोगों का ध्यान

मिल रहा है, हालांकि माही ने किसी में दिलचस्पी होने की बात स्वीकार नहीं की। उस समय उदित भी उनके आसपास ही थीं, जिन्होंने टिप्पणी की कि शायद माही का कोई खास इंसान यह शो देख रहा होगा। यह हल्की-फूल्की बातचीत जनवरी 2026 में माही और टेलीविजन अभिनेता जय भानुशाली द्वारा अपने 14 साल के वैवाहिक जीवन के अंत की घोषणा के कुछ महीनों बाद हुई है। पूर्व दंपति की एक बेटी तारा है और वे अपने गोद लिए बच्चों खुशी और राजवीर की परवरिश भी कर रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनके प्रशंसकों को उनके निजी जीवन को लेकर उत्सुकता है और वे उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, जय भानुशाली ने हाल ही में बताया कि बिग बॉस 20 में माही विज की भागीदारी ने उन्हें अपनी बेटी तारा के साथ अधिक समय बिताने का अवसर दिया है। इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों से बातचीत के दौरान जय ने बताया कि माही की अनुपस्थिति में तारा के साथ अधिक समय बिताने से उनका और तारा के साथ रिश्ता और मजबूत हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वह माही को रियलिटी शो में जारी रखना चाहते थे।

सूर्या: का दमदार टीज़र रिलीज

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के जन्मदिन पर उनकी आगामी फिल्म ‘सूर्या’-अंत से आरंभ तक ‘का दमदार टीज़र रिलीज कर दिया गया है। एम. पद्मकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल एक बिल्कुल अलग और गंभीर अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने अतीत के दर्द से जूझते हुए मेडिकल सिस्टम के भीतर छिपी एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने निकलता है। क्राइम थ्रिलर से भरपूर टीज़र में भावनात्मक उतार-चढ़ाव, जांच-पड़ताल, रहस्य और एक्शन की झलक देखने को मिलती है। 19 अक्टूबर को सनी देओल के जन्मदिन के मौके पर फिल्म के निर्माताओं ने इसका टीज़र जारी किया। इससे पहले फिल्म के मोशन पोस्टर को दर्शकों और अभिनेता के प्रशंसकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। पोस्टर में सनी देओल का रफ एंड टफ लुक, चेहरे पर उम्र का असर और उनकी गंभीर नजरें चर्चा में रही थीं। अब टीज़र ने फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। टीज़र से संकेत मिलता है कि ‘सूर्या’ की कहानी केवल एक व्यक्ति के संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं।



नेहा बोरा ने शांति मुचलका भरने से किया इनकार

नईदिल्ली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष शांति मुचलका भरने से शनिवार को इनकार कर दिया। इससे एक दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस के उस नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्हें 10,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का एक जमानती प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। बोरा ने नोटिस के औचित्य पर सवाल उठाते हुए पूछा, “मुझसे किसकी शांति बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है?” भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 के तहत 17 अक्टूबर को जारी पुलिस नोटिस में बोरा को 19 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष पेश होने और वजह स्पष्ट करने को कहा गया था कि “जांच की अवधि के दौरान शांति बनाए रखने” के लिए उनसे 10,000 रुपये का निजी मुचलका और एक जमानतदार देने के लिए क्यों न कहा जाए।

राहुल गांधी के इशारे पर कर काम रहे संजय राउत : भाजपा

मुंबई। भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि पार्टी को बदनाम करने के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे राहुल गांधी का हाथ है। भाजपा ने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत पर एक एआई-जनरेटेड ऑडियो क्लिप बनाने का आरोप लगाया, जिसमें मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे को 500 करोड़ रुपये दिए जाने का जिक्र है। भाजपा का दावा है कि इस कथित साजिश का मकसद भाजपा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और जरांगे के बीच दरार पैदा करना था, ताकि इससे कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) को राजनीतिक फायदा मिल सके। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बान ने मांग की है कि राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए (अगर जरूरी हो), और इस बात की जांच हो कि क्या शिवसेना (यूबीटी) सांसद को इस कथित ऑपरेशन के लिए (राहुल) गांधी से फंडिंग मिली थी। यहां पत्रकारों से बात करते हुए बान ने कहा, संजय राउत ने नवी मुंबई के वाशी में एक वॉर रूम से यह साजिश रची।

चुनाव आयोग चुनावी धांधली के सबूतों पर लें सज़ान : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से आग्रह किया कि वह उनकी पार्टी द्वारा जुटाई गई उन हजारों शपथ-पत्रों की जांच करे, जो कथित चुनावी गड़बड़ियों और अनियमितताओं से संबंधित हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल के घटनाक्रमों को एक अच्छी शुरुआत बताया और चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह पार्टी द्वारा जुटाए गए सबूतों पर कार्रवाई करे। यादव ने कहा कि खैर, यह एक अच्छी शुरुआत है – अब शायद चुनाव आयोग भी उन हज़ारों हलफनामों पर सज़ान लेगा, जिन्हें हमने चुनावी गड़बड़ियों और घोटालों के संबंध में इकट्ठा किया है। समाजवादी पार्टी ने लगातार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है। हाल के चुनावों में पार्टी ने अवसर मतदाताओं को रोकने, प्रशासन के पक्षपाती रवैये और मतदान के दौरान गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं।

मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की आहट ने जम्मू-कश्मीर की सियासत में हलचल तेज कर दी है। विधायकों में मंत्री की कुर्सी पाने की बेचैनी है, तो मौजूदा मंत्रियों को अपनी कुर्सी खिसकने का डर सता रहा है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अगले दो से तीन दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का ऐलान कर सियासी सरगमी बढ़ा दी है। अब हर किसी की निगाहें उस फैसले पर टिकी हैं, जो किसी की किस्मत चमका सकता है, तो किसी का सत्ता का सफर खत्म कर सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद यह अहम संकेत दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में बदलाव और नए मंत्रियों को शामिल करने के सिलसिले में उपराज्यपाल से चर्चा हो चुकी है। उमर ने उनसे अगले सप्ताह के शुरुआती दो-तीन दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय तय करने का आग्रह किया है।

यासीन मलिक और रशीद पर आरोप तय करने का निर्देश

नईदिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक, बारामूला के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए हवाला के जरिए पाकिस्तान से कथित तौर पर धन प्राप्त करने से जुड़े धन शोधन मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने आरोपियों के अपराध में शामिल होने का मजबूत संदेह व्यक्त करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पाते हुए सात आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि आरोपियों ने विभिन्न माध्यमों से 8.94 करोड़ रुपये की अपराध से आय अर्जित की, प्राप्त की, अंतरित की, छिपाई, अपने अधिकार में रखी और उसका इस्तेमाल किया। आरोपियों में प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक, अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह, बारामूला के सांसद शेख अब्दुल रशीद, मसरत आलम, जहूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर और मैसर्स टिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

भाजपा नेता रविशंकर का राहुल गांधी पर वार

कांग्रेस की 1 नवंबर की रैली को बताया सिखों का अपमान

नईदिल्ली। वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा 1 नवंबर को दिल्ली में विरोध रैली आयोजित करने की योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह तारीख सिख समुदाय के लिए संवेदनशील है। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली और कई अन्य शहरों में सिख विरोधी दंगे हुए थे, जिनमें सिख समुदाय को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया था। गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित करने का फैसला किया है।

नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, प्रसाद ने सवाल किया कि गांधी उसी दिन विरोध प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की सोच अराजकतावादी और माओवादी है। वह 1 नवंबर को अफरा-तफरी क्यों पैदा करना चाहते



हैं? यह निंदनीय है। उन्होंने इस महोत्सव की शुरुआत में विरोध प्रदर्शनों के दौरान गांधी द्वारा कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को घेरने की भी आलोचना की और इसे बेहद निंदनीय बताया। प्रसाद ने रैली करने के फैसले को बचकाना जिद करार दिया और कहा कि इससे गांधी का असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर वह सिखों का अपमान करना चाहते हैं, तो वह ऐसा करेंगे ही। प्रसाद ने दंगों की जांच करने वाले रंगनाथ मिश्रा आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि 2015 में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गठित एसआईटी की वजह से पीड़ितों को मुआवजा मिला और दोषियों को सजा हुई।

बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि दशहरा, नवरात्रि और छठ जैसे त्योहारों के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शनों से कर्नाट प्लेस, कमला नगर और खान मार्केट जैसे इलाकों के ञयापारी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि व्यापारियों के एक संगठन ने उन्हें बताया है कि ग्राहकों की संख्या में 70 प्रतिशत की गिरावट आई है, और उन्होंने 1 नवंबर के विरोध-प्रदर्शन की रद्द करने की मांग की है। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी गैर-जिम्मेदार हैं और लोगों की दुर्दशा के प्रति उदासीन हैं। इस तरह की अराजकता और अलोकतांत्रिक व्यवहार व्यापारियों के लिए चिंता का विषय है।

भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर और गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को सम्मान देने का उदाहरण दिया। प्रसाद ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के उस बयान को भी याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था, 84 की बात बार-बार क्यों उठाते हो? जो हुआ, सो हुआ।

कारोबारियों का राहुल को पत्र, महारैली

स्थगित करने की अपील

कहा- त्योहार का सीजन है, व्यापार प्रभावित होगा

नई दिल्ली। दिल्ली में त्योहारों के दौरान कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताते हुए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को 10 नवंबर के बाद आयोजित करने की अपील की है। सीटीआई की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि दिल्ली के व्यापारी इन दिनों दिवाली की खरीदारी और बिक्री के व्यस्त सीजन में हैं। ऐसे में रैली के कारण यातायात प्रभावित होने से व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी हो सकती है।

सीटीआई के अनुसार, धनतेरस, दिवाली और भाई दूज के आसपास दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयों और अन्य सामान की बिक्री बढ़ जाती है। त्योहारों से पहले बाजारों में ग्राहकों की भीड़ के साथ माल की आवाजाही भी तेज हो जाती है।

संगठन का कहना है कि रैलियों, मार्च और रास्ते बंद होने से पहले भी दिल्ली के कई इलाकों में व्यापार प्रभावित हुआ है। ऐसे में त्योहारों के दौरान यातायात बाधित होने से थोक और खुदरा कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पत्र में अक्तूबर में पहले ही 3 हजार करोड़ के हुए नुकसान की बात की गई। पत्र में लिखा, कर्नाट प्लेस, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली में लगातार रैलियों, मार्च और रास्ते बंद होने के कारण सीटीआई के आंकलन के अनुसार दिल्ली के व्यापारियों को पहले ही लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। थोक बाजारों में बाहर से माल आना बंद हो गया था और रिटेल में ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे थे।

पत्र में लिखा, रामलीला मैदान के पांच किमी के दायरे में दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध होलसेल एवं रिटेल बाजार स्थित हैं। चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, कश्मीरी गेट, नया बाजार, मोरी गेट, किनारी बाजार, दरीबा, दरिया गंज, अजमेरी गेट, जामा मस्जिद,



झंडेवालान, करोल बाग, नबी करीम, आजाद मार्केट, लाजपत राय मार्केट आदि स्थित हैं। इन बाजारों से पूरे भारत में माल जाता है। रैली के कारण ट्रैफिक डायवर्जन, मेट्रो स्टेशन बंद और बैरिकेडिंग से इन बाजारों का काम पूरी तरह ठप्प हो जाएगा।

संगठन ने यह भी आशंका जताई है कि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। सीटीआई ने राहुल गांधी से अपील की है कि व्यापारियों के हितों और त्योहारों के कारोबार को ध्यान में रखते हुए रैली को 10 नवंबर के बाद आयोजित किया जाए। वेणुगोपाल ने रामलीला मैदान में होने वाली रैली को प्रस्तावित %दिल्ली चलो मार्च% का समापन बताया। उन्होंने कहा कि यह मार्च 1 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचेगा। उन्होंने दावा किया कि इस रैली में कम से कम 10 लाख नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है।

उन्होंने दावा किया, मोदी-शाह के इशारे पर ज्ञानेश एंड कंपनी द्वारा अंजाम दी गई वोट चोरी के खिलाफ हमारे कार्यक्रम ऐतिहासिक होंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह रैली एक कड़ा संदेश देगी कि हम अपने लोकतंत्र की रक्षा करने और इन वोट चोरों को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट हैं।

इंडिया गठबंधन की इस रैली का मकसद सरकार पर दबाव बनाना है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ियां की गई हैं। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की है।

सपा-कांग्रेस का सीट बंटवारा गठबंधन में उलझा

अमेठी और रायबरेली की 10 सीटों पर कांग्रेस का दावा

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सपा व कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर उलझनें अब और बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस जितनी सीट मांग रही है, सपा उसकी एक तिहाई ही देने के मूड में है। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उभरती ताकत का असर यूपी में होने का दावा करते हुए कांग्रेस ने सीटों की डिमांड बढ़ाई है।



खास बात यह कि सपा की जीती सीटों में एक दर्जन पर कांग्रेस ने दावा ठोक है। इसमें सपा के बागी विधायकों वाली सीटें भी हैं। इस सवाल पर कि क्या गठबंधन पनपते अविश्वास व परस्पर विरोधाभासी बयानबाजी से हिचकोले खाने लगा है।

इसका जवाब सपा के वरिष्ठ नेता ने यह कहते हुए दिया कि चाय उतनी गर्म नहीं है जितनी केतली गर्म लग रही है। अमेठी व रायबरेली संसदीय सीटें कांग्रेस की बरसों से गढ़ रही हैं। विधानसभा चुनाव में सपा की स्थिति मजबूत रही है और वह भाजपा को चुनौती देती है। लेकिन कांग्रेस ने इन दोनों जिलों की 10 विधानसभा सीटें मांगी हैं।

अमेठी में पिछले चुनाव सपा ने तीन और भाजपा ने दो सीटें जीती थीं। रायबरेली की पांच में चार सपा के पाले में और एक भाजपा के पाले में थी। सपा ने पहले से तय किया है कि उसके

साथ छोड़ कर भाजपा का दामन थामने वाले बागी विधायकों को वह खुद हराएगी।

इनमें ऊंचाहार से जीते मनोज पांडेय जो योगी सरकार में मंत्री हैं, खास तौर पर सपा के निशाने पर हैं। राकेश प्रताप सिंह अमेठी से पिछली बार सपा से जीते थे। वह भी भाजपा में जा चुके हैं। सपा ने यह सीटें देने से इन्कार का संदेशा भिजवा दिया है।

कांग्रेस ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए ताकत झोंक दी है और इसमें इंडिया ब्लाक के सभी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। विपक्षी राजनीति में अगुवा की भूमिका में अब रैली के जरिये इंडिया ब्लांक की एकजुटता का संदेश तो भाजपा को दिया जाएगा ही साथ छुपा हुआ संदेश यूपी चुनाव के लिए भी होगा। इससे अपने पक्ष में माहौल बना कर सपा से अधिक से अधिक सीटें लेने का दबाव बनाया जा सके।

स्टोल प्रमुख समाचार

दक्षिण अफ्रीका को झटका स्टार तेज गेंदबाज बाहर

केप टाउन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों



की टेस्ट सीरीज के निर्णायक मुकाबले से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे ग्रीडन में हल्की चोट के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं।

क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं करने का फैसला किया है।

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। सीरीज का निर्णायक मुकाबला मंगलवार से केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी, ऐसे में नॉर्टजे की गैरमौजूदगी मेजबान टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी।

एनरिक नॉर्टजे को गकेबरहा में खेले गए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में गेंदबाजी करते समय चोट लगी थी। बुधवार को चोटिल होने के बाद वह चौथे दिन सुबह अपने चौथे ओवर के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए थे। अगले दिन कराए गए स्कैन में उनकी चोट की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें निर्णायक मुकाबले से बाहर रखने का फैसला लिया गया।

नॉर्टजे के लिए यह चोट इसलिए भी निराशाजनक है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लंबे अंतराल के बाद वापसी की थी। दरबान में सीरीज के पहले टेस्ट से पहले उन्होंने साढ़े तीन साल से ज्यादा समय तक कोई रेड-बॉल मुकाबला नहीं खेला था। दूसरे टेस्ट में भी उनके खेलने को लेकर आशंका थी, लेकिन पहले मैच में फिट रहने के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में बरकरार रखा गया था।

निर्णायक टेस्ट में नॉर्टजे की जगह भरने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पास कई विकल्प हैं। तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएल्ट्जी, ऑलराउंडर कॉर्बिन शॉश और डेन पैटरसन में से किसी एक को मौका मिल सकता है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

कोटक महिंद्रा बैंक का मुनाफा दूसरी तिमाही में 26% बढ़ा

मुंबई। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में 26 प्रतिशत बढ़कर 5,645 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने शनिवार को बताया कि उसने एकल आधार पर 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,212 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया। कोटक महिंद्रा बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 16 प्रतिशत बढ़कर 8,459 करोड़ रुपए रही। शुद्ध अग्रिम में 25 प्रतिशत की वृद्धि से इसे समर्थन मिला, हालांकि शुद्ध ब्याज मार्जिन में 0.23 प्रतिशत की गिरावट ने इस वृद्धि को कुछ सीमित किया। बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की रियायती स्वेप सुविधा के तहत 55,344 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्रवासी (बैंकिंग) यानी एफसीएनआर (बी) जमा जुटाने के कारण समीक्षाधीन तिमाही में शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव पड़ा।

गहरे समुद्र में तेल-गैस खोज का जोखिम घटाएगी सरकार

नई दिल्ली। सरकार 84,084 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन योजना के तहत गहरे समुद्र में तेल एवं गैस की खोज के जोखिम को कम करने के लिए कंपनियों को वित्तीय सहायता देगी। इसके तहत 56 खोजी कुओं की लागत का 50 प्रतिशत तक और चार भूवैज्ञानिक अध्ययन वाले कुओं की लागत का पूरा खर्च निर्धारित सीमा के भीतर सरकार उठाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने योजना के संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज को प्रोत्साहन देना और आयातित हाइड्रोकार्बन पर भारत की निर्भरता को कम करना है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मिश्र ने दिशानिर्देशों की प्रस्तावना में समुद्र मंथन योजना को हाल के वर्षों में तेल एवं गैस की खोज और उत्पादन के क्षेत्र में सबसे महत्वाकांक्षी पहल बताया।

चीन की अर्थव्यवस्था में निर्यात बढ़ा फिर भी कंपनियां घाटे में

बीजिंग। चीन के औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को ताकत दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अमेरिका समेत कई देशों के नीति-निर्माताओं को आशंका है कि चीनी सामान की बाढ़ उनके घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकती है, रोजगार घटा सकती है और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए उन्हें चीन पर निर्भर बना सकती है। लेकिन चीन की औद्योगिक ताकत के पीछे एक विरोधाभास भी उभर रहा है। देश की कई फैक्ट्रियां बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात करने के बावजूद मुनाफा कमाने में नाकाम हो रही हैं। लंदन स्थित शोध संस्था केपिटल इकोनॉमिक्स के अनुसार, चीन की उन औद्योगिक कंपनियों का अनुपात, जो घाटे में चल रही हैं, 2018 के मुकाबले दोगुना होकर इस साल 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यानी औद्योगिक क्षेत्र की करीब हर तीन में से एक कंपनी नुकसान उठा रही है।

जेके टायर कंपनी का कीमतों में 4-5% बढ़ोतरी का प्लान

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों और कच्चे माल की बढ़ती लागत का असर अब गाड़ियों के मेंटेनेंस पर भी पड़ने लगा है। देश की प्रमुख टायर निर्माता कंपनी जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में टायरों की कीमतों में 4-5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत और कंटेनर दुलाई महंगी होने के कारण कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। जेके टायर के प्रबंध निदेशक अंशुमान सिंघानिया ने कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद बताया कि तीसरी तिमाही में टायरों की कीमतों में 4-5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने की योजना है। इससे पहले पहली तिमाही में कंपनी ने कीमतें 5 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 7 प्रतिशत बढ़ाई थीं।

नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके रुपये को तलाशने दें रास्ता

(आरईईआर) सहित कई अनुमानों के अनुसार रुपया अधिक मूल्यांकित नहीं है बल्कि इसका मूल्यांकन कम भी हो सकता है।'

वर्ष 2025 में कैलेंडर वर्ष के दौरान रुपये में लगभग 4.7 फीसदी की गिरावट आई। वहीं इस साल मई में रुपया 96.96 रुपये प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया, जो 7.3 फीसदी की गिरावट को दर्शाता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने एफसीएनआर (बी), बाहरी वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा में लिए जाने वाले विदेशी उधार के लिए डॉलर-रुपया स्वेप की तीन-भाग वाली व्यवस्था की घोषणा की। ये सुविधाएं 8 जून को शुरू हुईं। एफसीएनआर (बी) सुविधा को तय समय से एक महीने पहले 31 अगस्त को ही बंद कर दिया गया क्योंकि इसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इस पूरी योजना के तहत कुल 143.6 अरब डॉलर जुटाए गए जिनमें से 132.98 अरब



डॉलर एफसीएनआर (बी) माध्यम से आए। इससे भी रुपये में गिरावट नहीं थम सकी। जून के अंतिम सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 667 अरब डॉलर था। एफसीएनआर (बी) के जरिए आए धन के चलते सितंबर के पहले सप्ताह में यह बढ़कर 785.7 अरब डॉलर हो गया। लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आई और 9 अक्टूबर को यह 726.3 अरब डॉलर रह गया। यानी महज छह सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 60 अरब डॉलर की कमी आई।

चीन का अनुसरण करते हुए केंद्रीय बैंक ने 20 लाख डॉलर से अधिक के प्रत्येक

विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स अनुबंध पर 20 फीसदी नकद आरक्षित रखने की अनिवार्यता लागू की। इसे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिजर्व (एफईआरआर) कहा गया है। इसके तहत बैंकों को अपने कुल जोखिम के एक निश्चित हिस्से के बराबर राशि अलग रखकर रिजर्व बैंक के पास जमा करनी होती है। दूसरे चरण में एफईआरआर का दायरा बढ़ाकर उन नॉन-डिलिवरेबल अनुबंधों को भी शामिल कर लिया गया, जिनमें अनिवासी ग्राहकों के लिए रुपये से जुड़े लेनदेन के जोखिम से बचाव की व्यवस्था होती है। बैंक किसी कर्रपोरेट ग्राहक को विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंध रह किए जाने के बाद उसे दोबारा बुक करने की अनुमति नहीं दे सकते। यह नियम डिलिवरेबल और नॉन-डिलिवरेबल दोनों तरह के बाजारों पर लागू होता है। हालांकि परिपक्वता अवधि पूरी होने पर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों को आगे बढ़ाने (रोलओवर) की अनुमति जारी रहेगी। साथ

ही रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की डॉलर संबंधी मांग को पूरा करने के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की है। इन सुविधा उपायों का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है। हमें मुद्रा बाजार में स्थिरता चाहिए लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। बैंकों को रिजर्व बैंक के पास 20 फीसदी राशि एफईआरआर के रूप में रखनी होगी। वे उस पैसे का इस्तेमाल कर्ज देने के लिए नहीं कर पाएंगे। निर्यातक अपने कमाए हुए डॉलर जल्दबाजी में नहीं बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रुपया आगे और कमजोर होगा। दूसरी ओर आयातक भी इसी आशंका के चरिते जरूरत से ज्यादा हेंजिंग कर रहे हैं। इससे बाजार में डॉलर की आपूर्ति और मांग के बीच अंतर पैदा हो रहा है। अभी एक ही विकल्प है। रुपये को अपना वास्तविक स्तर खोजने दें लेकिन यह प्रक्रिया नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री साय ने मंदिर परिसर में 50 लाख रुपये की लागत से भव्य डोम निर्माण की घोषणा की

सुशासन व पारदर्शिता के साथ हर वर्ग तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता : साय

महासमुंद। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत गढ़फुलझर में बाबा बिशासहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्वमंगल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने समाज की मांग पर मंदिर परिसर में 50 लाख रुपये की लागत से भव्य डोम निर्माण की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्ष 2024 में गढ़फुलझर के विकास के लिए किए गए वादे अब धरातल पर साकार हो रहे हैं। सर्वमंगल भवन का निर्माण पूरा होने से सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही 48 लाख रुपये की लागत से मानसरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में लगभग पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी



प्रगति पर है, जिस पर लगभग 3.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से गढ़फुलझर और आसपास के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि गढ़फुलझर में विकास का बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है

और आने वाले समय में क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को और गति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कोलता समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि समाज का राज्य सरकार को सदैव स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। कोलता समाज मेहनतकश, शिक्षित, समृद्ध और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित

समाज है। कृषि, शिक्षा, सेवा और सामाजिक क्षेत्र में समाज के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता और आपसी सहयोग को मजबूत करने में कोलता समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपनी प्रगतिशील सोच और सामाजिक चेतना के कारण यह समाज दूसरे समाजों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार जनकल्याण से जुड़े संकल्पों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। सरकार का लक्ष्य विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उल्लेख करते हुए कहा कि आवास से वंचित गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में लागू जीएसटी देश का सबसे बड़ा कर सुधार : वित्त मंत्री

प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य

रायपुर। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा कर सुधार है। जीएसटी ने देश की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाया है। इससे न केवल व्यापारियों और उद्यमियों को राहत मिली है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग कर प्रशासन तथा कर संबंधी सेवाओं को और अधिक सरल, सटीक एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वित्त मंत्री श्री चौधरी आज दुर्ग जिले के अंजोरा स्थित पृथ्वी पैलेस में टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ टैक्स टेक समिट 2026 को संबोधित कर रहे



थे। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री एवं दुर्ग विधायक श्री गजेंद्र यादव तथा जीएसटी अपीलीय अधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष श्री संजय कुमार मिश्रा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कर विशेषज्ञ, अधिवक्ता और टैक्स प्रैक्टिशनर्स उपस्थित थे।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले देश में 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और 23 प्रकार के उपकर प्रचलित थे। अलग-अलग कर व्यवस्थाओं के कारण व्यापारियों को अनेक प्रक्रियागत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने इन

करों को एकीकृत कर देश को एक साझा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था प्रदान की है। इससे कर अनुपालन की प्रक्रियाएं सरल हुई हैं, कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से व्यापारियों पर कर अनुपालन का बोझ कम करने तथा कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। भारतीय उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा करने के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं।

साय जी आप मुख्यमंत्री है तो कांग्रेस की आदिवासी समाज के उत्थान की नीति के कारण : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री साय ने बयान दिया है कि 50 सालों में कांग्रेस ने जनजातियों के लिए कुछ नहीं किया। साय जी जान ले 50 सालों में कांग्रेस ने आदिवासियों की संस्कृति को बचाये रखा, आदिवासी को जनजाति नहीं बनने दिया। पेसा कानून संविधान में विशेष अधिकार नौकरी में आरक्षण, विधानमंडल में आरक्षण सब कांग्रेस की देन है। साय जी आप आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है तो इसके पीछे भी कांग्रेस की नीतियां ही हैं। कांग्रेस ने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक आदिवासी



नेता के रूप में प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना भी उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत को दर्शाता है, जिसमें आदिवासी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर प्राप्त हुए हैं। इस व्यवस्था की नाँव भारतीय संविधान ने रखी, जिसे बनाने में कांग्रेस की निर्णायक भूमिका रही। कांग्रेस ने आदिवासियों को

लाखों वनाधिकार पट्टे दिये। बस्तर का स्वाभिमान, नंदराज पर्वत को बचाये रखा, जिसे भाजपा के डबल इंजन सरकार ने आजनी के चरणों में समर्पित कर दिया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भारत में आदिवासी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, सरकारी नौकरियों में अवसर, जल-जंगल-जमीन के अधिकार और संवैधानिक संरक्षण दिलाने में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका रही है। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व जिस संवैधानिक व्यवस्था के कारण संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री साय से सांसद धर्मेन्द्र प्रधान ने की शिष्टाचार भेंट



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं ओडिशा के संबलपुर से सांसद धर्मेन्द्र प्रधान ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने श्री प्रधान का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच विभिन्न संसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में गांवों के विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को मिल रही प्राथमिकता : टंकराम

बलौदाबाजार। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना विकास को निरंतर गति दे रही है। इसी कड़ी में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने शनिवार को बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम पौंसरी, मगरवाय, बुड़गहन और पूरना में लगभग 70 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों की मांगों को प्राथमिकता देते हुए लगभग 57 लाख रुपए के नए विकास कार्यों की घोषणा भी की। इस प्रकार ग्राम गांवों को स्तरीय



1 करोड़ 32 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगत मिली। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने ग्रामीणों की मांग पर ग्राम पौंसरी में 10 लाख रुपए की लागत से शोध निर्माण और 5 लाख रुपए से बाईंड़ीवाल निर्माण की घोषणा की। इसी प्रकार ग्राम मगरवाय में

10 लाख रुपए से शोध निर्माण, ग्राम बुड़गहन में 20 लाख रुपए से चेक डेम निर्माण तथा ग्राम पूरना में 7 लाख रुपए से अतिरिक्त कक्ष और 5 लाख रुपए से रंगमंच निर्माण की घोषणा की। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं, जल संरक्षण और

शैक्षणिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

विभिन्न ग्रामों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि गांवों का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रहे निर्माण कार्य इस बात का प्रमाण हैं कि विकास की योजनाएं धरातल पर साकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

सेवा सेतु केन्द्र : दिलीप कुमार को एक दिन में मिला जाति प्रमाण पत्र

रायपुर। आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का त्वरित एवं पारदर्शी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 'सेवा सेतु' केन्द्र जमीनी स्तर पर बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिल रही



है। बालोद जिले के ग्राम मुख्देगुड़ा निवासी श्री दिलीप के लिए यह अत्यंत मददगार साबित हुआ, जहां उन्हें मात्र एक ही दिवस के भीतर उनका जाति प्रमाण पत्र तैयार कर प्रदान कर दिया गया। हितग्राही दिलीप कुमार ने बताया कि उन्हें विभिन्न आवश्यक कार्यों एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की अत्यंत आवश्यकता थी। पूर्व में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी तथा बार-बार कार्यालयीन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन सेवा सेतु केन्द्र के तहत जब उन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए, तो संबंधित अमले ने पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता दिखाते हुए आवेदन का त्वरित सत्यापन किया और रिकॉर्ड समय में मात्र एक दिन के भीतर उनका जाति प्रमाण पत्र तैयार कर उन्हें सौंप दिया। एक ही दिन में बिना किसी परेशानी के प्रमाण पत्र मिलने पर दिलीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

स्मृति ईरानी को कार्यकर्ताओं के असंतोष का सामना करना पड़ेगा : कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की नवनियुक्त प्रभारी स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ आ रही हैं, उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत है। स्मृति ईरानी को भाजपा की गुटबाजी कार्यकर्ताओं के असंतोष का सामना करना पड़ेगा। स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ में भाजपा



की सरकार प्रदेशवासियों के लिए सिर दर्द बन चुकी है। यह सरकार पौने तीन सालों में जनता का भरोसा खो चुकी है। सरकार में भ्रष्टाचार हावी है, कमीशनखोरी सरकार में बैठे लोगों का लक्ष्य बन गया है। उम्मीद है कि आप भाजपा सरकार को उसका कर्तव्य याद दिलाने का प्रयास जरूर करेंगी। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रभारी के रूप में स्मृति ईरानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश भाजपा की गुटबाजी से निपटना और कार्यकर्ताओं के असंतोष का सामना करना होगा। भाजपा सरकार में मंत्रियों में आपसी सिर फुटव्वल है। मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावती तेवर में है। वरिष्ठ विधायकों, नेताओं को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। भाजपा कार्यकर्ता सरकार के ढाई साल के कार्यकाल से नाराज हैं। सरकार में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है।

मनियारी नदी और डोंगानाला पर बनेंगे पुल, 14.26 करोड़ मंजूर

रायपुर। सड़क संपर्क और आवागमन की सुविधाओं को मजबूत करने लोक निर्माण विभाग ने मुंगेली और बिलासपुर जिलों में दो नए उच्च स्तरीय पुलों के लिए राशि मंजूर की है। दोनों पुलों और उनके पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए कुल 14 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपए की प्रशासकीय

भाजपा सरकार ने महिलाओं से धोखा दिया : कांग्रेस

रायपुर। भाजपा सरकार महिलाओं को धोखा दे रही है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को धोखा दिया, पहले रोजगार का वादा कर वोट लिया अब भूल गए। सरकार की बदनीयती के कारण प्रदेश की 3 लाख से अधिक महिलाएं जो स्व

भूस्खलन के एक महीने बाद रेल यातायात बहाल हुआ, मालगाड़ियां शुरू हुईं

जगदलपुर। चक्रवात से हुई बारिश से ओडिशा के मालिगुड़ा क्षेत्र में 24 सितंबर को भारी भूस्खलन हुआ था। इससे तीन स्थानों पर रेलवे ट्रैक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद बस्तर से रेल यातायात पूरी तरह ठप था। रेलवे विभाग के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के. संदीप के अनुसार रेलवे के इंजीनियरिंग और सिग्नल टीमों ने मिलकर ट्रैक को 24 अक्टूबर को बहाली का काम पूरा कर लिया गया। इसके बाद मालगाड़ियों को चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन यात्री ट्रेनें सुरक्षा कारणों से चलने की अनुमति नहीं दी गई है, आगे सब कुछ ठीक रहा तो यात्री ट्रेनें भी बहाल कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अब मालगाड़ियों के चलने से राहत की उम्मीद है। यात्री ट्रेनें बहाल करने से पहले रेलवे सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद निर्णय लिया जायेगा है।

एक महीने तक ट्रेनें बंद रहने से बैलाडीला के एनएमडीसी का लौह अयस्क की दुलाई रुक गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनएमडीसी का लगभग 411 करोड़ रुपये का लौह अयस्क परिवहन प्रभावित हुआ है। एनएमडीसी की छत्तीसगढ़ इकाई की लौह अयस्क बिज्जी में सितंबर माह में गिरावट दर्ज की गई। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2026 में बिज्जी 21.3 लाख टन रही, जबकि सितंबर 2025 में यह 25.8 लाख टन थी। यानी सालाना आधार पर 4.5 लाख टन की कमी आई।



सहायता समूह के माध्यम से रोजगार प्राप्त करती थी, बेरोजगार हो गयी है। भाजपा सरकार चुनाव में वादा करने के बाद उनको काम नहीं दे रही है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में वादा किया था पूरे प्रदेश में महिला समूहों को रेडी टू इंट का काम दिया जाएगा। सरकार में आने के बाद इसको भूल गए। जब विपक्ष और महिलाओं ने मांग किया तब एक साल पहले घोषणा किया कि पहले 6 जिलों में महिलाओं को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में काम देंगे, फिर सभी जिलों में देंगे। ढाई साल हो गया सिर्फ रायगढ़ जिले के कुछ प्रोजेक्ट में केवल 10 समूहों को एवं दंतवाड़ा जिले के कुआंकोंडा ब्लॉक में काम दिया गया, पूरे जिले में नहीं। सभी 6 जिले की महिलाएं आज भी काम के इंतजार में हैं। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि जब 6 जिले में ढाई साल में काम नहीं दे पाए, तब पूरे प्रदेश में क्या देंगे?

छत्तीसगढ़ में नवाचार, अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर विकसित कर रहा आईआईटी भिलाई

आईआईटी भिलाई के छठे दीक्षांत समारोह में 313 विद्यार्थियों को मिली उपाधियां

रायपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई के नालंदा हॉल में आज छठा दीक्षांत समारोह गरिमाय वातावरण में आयोजित हुआ। समारोह में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कुल 313 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं सीनेट पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के पूर्व सदस्य एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व महानिदेशक डॉ. विजय कुमार सारस्वत उपस्थित रहे। कार्यक्रम

की अध्यक्षता आईआईटी भिलाई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष प्रो. वीरेंद्र कुमार विजय ने की। समारोह का शुभारंभ अकादमिक शोभायात्रा के साथ हुआ। आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने स्वागत उद्घोषण देते हुए संस्थान की वार्षिक उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़ को प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने बताया कि आईआईटी भिलाई



और छत्तीसगढ़ शासन की संयुक्त पहल से राज्य का पहला आईटी पार्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा

की महत्वपूर्ण पहल है। संस्थान का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान इकोसिस्टम विकसित करना है। उन्होंने बताया कि आईआईटी भिलाई में वर्तमान में 191 अनुसंधान परियोजनाएँ संचालित हैं तथा संस्थान का अनुसंधान एवं विकास बजट बढ़कर 187 करोड़ रुपए हो गया है। अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को विस्तार देते हुए संस्थान ने आईएमटी नॉर्ड यूरोप, इकोल सेंट्राल दी नांत और ग्राज प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

बस्तर के लालबाग में वनोपज से सजी 20,700 वर्गफीट की भव्य रंगोली ने रचा विश्व रिकॉर्ड

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अवलोकन

जगदलपुर। बस्तर जिले के जिला मुख्यालय जगदलपुर का लालबाग का मैदान शुक्रवार की सुबह एक अलग ही रंग ले चुका था। यहाँ मैदान का एक बड़ा हिस्सा कैनवास बन चुका था और उसमें वनोपज व अनाज रंग बन चुके थे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बस्तर दशहरा के मौके पर बस्तर आगमन पर यह अनोखी और अद्वितीय कलाकृति वन विभाग की ओर से तैयार कराई गई थी। 15 से अधिक वनोपज व अनाज का इस्तेमाल करते हुए 20,700 वर्गफीट क्षेत्रफल में सुंदर आकृतियां उकेरी गई थीं। इसका



अवलोकन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं अन्य अतिथियों ने किया। वनोपज से रंगोली की विशिष्टता को देखते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इस अद्भुत रंगोली को प्रमाणित भी किया गया। गौरतलब है कि बस्तर दशहरा के दौरान पहली बार देश के प्रथम

नागरिक का आगमन माई दंतेश्वरी की धरा पर हुआ। दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंची राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 23 अक्टूबर को जगदलपुर आगमन हुआ। यहाँ माई दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेने के बाद वे मुरिया दरबार में शामिल हुईं, फिर लालबाग मैदान में सभा को सम्बोधित करने पहुँचीं। उनके इस प्रवास को लेकर बस्तर में उत्साह दिखा। इसी बीच वन विभाग ने नक्सलवाद के खात्मे के बाद बदलते बस्तर की तस्वीर को रंगोली के माध्यम से राष्ट्रपति के समक्ष रखा। बस्तर की समृद्ध जनजातीय विरासत, विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं, प्राकृतिक संपदा तथा क्षेत्र की विकास यात्रा को रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।